राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 240 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली,बुधवार, 24 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

उन्नाव मामला : इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजी गई पत्र याचिका

प्रयागराज। उन्नाव के बबुरहा गांव के एक खेत में तीन नाबालिग दलित लड़कियां संदिग्ध परिस्थितियों में बेसुध पाई गई थीं। इनमें से दो की मौत हो चुकी थी और एक इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। इस मामले को अपने संज्ञान में लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका भेजी गई है। याचिका पर प्रतिक्रिया का मिलना अभी बाकी है। एकीकृत जन आंदोलन की अध्यक्ष नीलिम दत्ता द्वारा भेजी गई इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले पर उन्नाव पुलिस न्याय करेगी, इस पर किसी को भरोसा नहीं है। रविवार को उन्नाव पुलिस ने उन पर अपने ट्वीट्स के माध्यम से 'भ्रामक जानकारियां' फैलाने के आरोप में एक मामला भी दर्ज किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले को संज्ञान में लेने और इसे अपनी देखरेख में लेने, इसकी जांच करने और इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि इस मामले में अकेले बचीं नाबालिग लड़की को एयर-एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाए।

भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने पर जोर, 13500 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली। देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार का बड़ा और अहम फैसला लिया गया। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 13 हजार 500 करोड़ के रक्षा खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने खरीद को मंजूरी दी। 118 अर्जुन मार्क-1 ए टैंक के लिए ये मंजूरी दी गई है। सेना के लिए 820 बख्तरबंद गाड़ियां भी ली जाएंगी। रक्षा क्षेत्र में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। 8379 करोड़ रूपये 118 अर्जुन मार्क-1 ए टैंक के लिए मंजूर किए गए जबकि 820 बख्तरबंद गाड़ियों के लिए 5300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ऐसे में जबकि लगातार केंद्र सरकार की ओर से ये दावा किया जाता रहा है कि सुरक्षा को लेकर आत्मनिर्भर बनना हमारा पहला लक्ष्य है। इसे उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा किया स्वीकार

पुडुचेरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा में विश्वासमत गंवाने के एक दिन बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, ''राष्ट्रपति ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी समेत उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा 22 फरवरी से स्वीकार कर लिया है।'' पुडुचेरी की उपराज्यपाल के राजनिवास द्वारा अधिसूचना की एक प्रति मीडिया को उपलब्ध करायी गयी। मुख्य सचिव अश्वनी कुमार ने कहा कि पुडुचेरी सरकार के गजट में अधिसूचना पुर्नप्रकाशित की गयी है। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी के इस्तीफे के कारण सोमवार को पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार गिर गई।

हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेसः भूपेन्द्र सिंह हुड्डा

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि अगले महीने शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन की मांग भी रखेगी ताकि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके। अपने आवास पर बैठक के बाद हुड्डा ने कहा, ''विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस एपीएमसी कानून में संशोधन की मांग भी रखेगी ताकि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके।''

जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती : मोदी

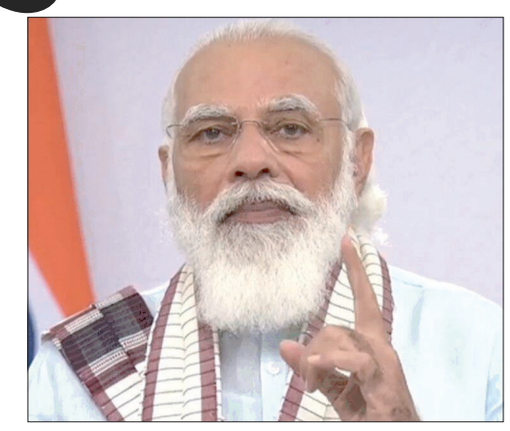

खड़गपुर, (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन और इसके कारण उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं ने विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न की है, ऐसे में आईआईटी को आपदा के प्रभावों का सामना करने में सक्षम आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यह विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का सुरक्षित एवं वहनीय पर्यावरण अनुकूल विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया।

पीएम ने आपदा सहने में सक्षम आधारभूत ढांचे पर वैश्विक गठबंधन (सीडीआरआई) का जिक्र किया जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में भारत ने दुनिया का ध्यान आपदा प्रबंधन के मुद्दे पर दिलाया है। आपने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड में क्या हुआ। हमें आपदा सहने में सक्षम आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को बर्दाश्त कर सके। उन्होंने कोविड-19 से मुकाबले के लिये आईआईटी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और उसकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थानों को अब स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी समस्याओं का भविष्योन्मुखी समाधान तलाशने के लिये तेजी से काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा, आप भारत के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो सोचा है, आप जिस नवाचार पर काम कर रहे हैं, संभव है उसमें आपको पूरी सफलता ना मिले, लेकिन आपकी उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे। मोदी ने कहा, 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और आकांक्षाएं भी बदल गई हैं। अब आईआईटी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के रूप में अगले स्तर पर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी प्रौद्योगिकी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, टिकाऊ हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्शे और भूस्थानिक आंकड़ों को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है।

इस कदम से प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी को बहुत मजबूती मिलेगी। मोदी ने कहा, इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा स्टार्टअप और नवोन्मेषकताओं को नई आजादी मिलेगी। उन्होंने छात्रों से कहा कि जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है, गलत है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे बहुत से सवाल आएंगे। इन सवालों का उत्तर तीन आत्म (सेल्फ थ्री) में हैं। ये हैं- आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निःस्वार्थ भाव। आप अपने सामर्थ्य को पहचानकर आगे बढ़ें, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि आप सभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के जिस मार्ग पर चले हैं, वहां जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है।

रुजिरा के जवाबों से संतुष्ट नहीं सीबीआई टीम

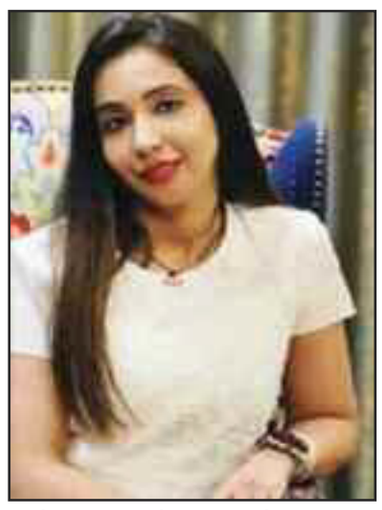

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ सीएम ममता बनर्जी के टीएमसी सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के कोयला घोटाले में संलिप्तता को लेकर उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई की टीम उनके घर से निकल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, रुजिरा से पूछताछ से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है। रुजिरा ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। सूत्रों ने बताया कि बैंक अकाउंट से जुड़े सवालों पर जानकारी न होने की बात को टाल गईं, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और निकल गए। उनके बाहर आते ही अब सीबीआई की टीम दाखिल हो गई है। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सोमवार को समन जारी किया गया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को अभी फिलहाल समन नहीं दिया गया है। नरूला से पूछताछ के बाद अभिषेक को जल्द ही समन दिया जा सकता है। सीबीआई की कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। सोमवार को सीबीईआई का नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्हें देश के कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इन हथकंडों का इस्तेमाल कर डराने की कोशिश की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, गवाहों और संदिग्धों के कुछ बयानों में रुजिरा की भूमिका सामने आई है। सीबीआई को जांच के दौरान पता चला है कि रुजिरा की कंपनी के अकाउंट में कुछ ऐसे लेनदेन हुए हैं, जिनके तार सीधे तौर पर कोल स्कैम से जुड़े हैं। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने अपनी मां लता के नाम से साल 2010 में लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विस फर्म की शुरूआत की थी। 4 मई, 2011 को इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। साल 2013 में माकपा की ओर से भी आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी की मदद से अभिषेक ने अपनी फर्म का इस्तेमाल पोंजी स्कीम में किया। आरोप ये भी है कि कुछ ही सालों में इस फर्म का कारोबार 300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सीबीआई की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा है कि वो डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें जेल से डराने की कोशिश न करें, हमने बंदूकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम चूहों के खिलाफ लड़ाई से नहीं डरते। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी डर या धमकी से नहीं डरने वाली।

सतर्कता ना छोड़ें, कोरोना से बचाव की सावधानियों को अपनाएं : शिवराज सिंह चौहान

भोपाल।मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों में लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा।इसके साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी।यह फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया है।

बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है। मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल में तत्काल मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाराष्ट्र से लगे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश भी दिए।

कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय में आयोजित बैठक में आज सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक तत्काल आयोजित करें तथा जिला स्तर पर विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सावधानी के संबंध में तत्काल निर्णय लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरात्रि पर्व पर होने वाले मेलों के संबंध में सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। विशेषकर महाराष्ट्र से लगे जिलों में आयोजित होने वाले मेलों में सहभागिता के संबंध में आरटी पीसीआर के परीक्षण की अनिवार्यता पर भी विचार किया जाना चाहिये।

बैठक में इंदौर और भोपाल से राज्य के अन्य भागों में होने वाले आवागमन पर सतर्कता के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ ।

उल्लेखनीय है कि अचानक कोरोना के मामले बढ़ने से सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी है।भोपाल और इंदौर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में एक हैं।खुद मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्री कोरोना का शिकार हो चुके हैं।

टूलकिट केस : दिशा रवि की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपये का मुचलका भरने की शर्त पर मिली बेल

नई दिल्ली, (संवाददाता)। किसान आंदोल से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने रवि को 1 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने रवि को एक लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानती जमा करने को कहा है। टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। रवि और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है कि दिशा रवि के वकील ने शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से कहा था कि यह दशार्ने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा टूलकिट 26 जनवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। दिशा ने अपने वकील के जरिये अदालत से कहा था कि यदि किसानों के प्रदर्शन को वैश्विक स्तर पर उठाना राजद्रोह है, तो मैं जेल में ही ठीक हूं। दिल्ली पुलिस द्वारा दिशा की जमानत याचिका का विरोध किए जाने के बाद दिशा के वकील ने यह दलील दी। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक टूलकिट नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। दिशा ने वॉट्सऐप पर हुई चैट (बातचीत) मिटा दी थी, वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे यह जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था। खालिस्तान के संबंध में दिल्ली पुलिस का कहना है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वैंकूवर एक अहम स्थान है और किसान एकता कंपनी नामक एक संगठन वैंकूवर में एक अन्य संगठन के संपर्क में है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा कि 26 जनवरी की हिंसा के साथ टूलकिट के संबंध में आपने क्या सबूत जुटाए हैं दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और हमें सबूतों की खोज करनी है। दिशा रवि की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि दिशा का खालिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है और सिख फॉर जस्टिस या पीजेएफ से भी उनका कोई कनेक्शन नहीं है।

कांग्रेसमुक्त हुआ सूरत नगर निगम, भाजपा को 93 और आप ने जीती 27 सीटें

अहमदाबाद, (एजेंसी)। दक्षिण गुजरात की सूरत महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस जबर्दस्त झटका लगा है। सूरत ही नहीं राज्य के सभी 6 नगर निगमों में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। कांग्रेस का सबसे बुरा हाल सूरत महानगर पालिका में हुआ है, जहां उसका खाता भी नहीं खुला। पाटीदारों का गढ़ माने जाते सूरत में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी प्रमुख हार्दिक पटेल भी पार्टी को सफलता दिलाने में नाकाम हुए हैं। 2015 के पाटीदार आंदोलन के एपी सेंटर रहे सूरत में गत चुनाव में कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थीं। पाटीदार आंदोलन के बावजूद भाजपा 79 सीटें जीतने में सफल रही थी। 120 सीटों वाले सूरत नगर निगम में भाजपा ने 93 और आप ने 27 सीटें जीती हैं। गुजरात में पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ने वाली आप खासकर सूरत में कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरी है। हांलाकि सूरत को छोड़ अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, जामनगर ओर भावनगर नगर निगम में आप का खाता नहीं खुला है। लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। गुजरात के नतीजों से गदगद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि नई राजनीति की शुरूआत के लिए गुजरात के लोगों से हृदय से अभिनंदन। बता दें कि मतदान से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था एक मौका आप को, फिर देखो गुजरात को। सूरत नगर निगम में सत्ता तो नहीं मिली लेकिन आप विपक्ष बनकर उभरी है। गुजरात में पहली बार कोई तीसरा राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आप को सूरत में कांग्रेस वोटरों में सेंध लगाने में सफल रही है। साथ ही उम्मीदवारों के चयन में पास बनाम कांग्रेस की लड़ाई का भी आप को सूरत में फायदा हुआ है। इसके अलावा आप के गुजरात प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया सूरत के मूल निवासी हैं और पाटीदार समाज से आते हैं। इन सभी का सूरत में आप को फायदा हुआ है और कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान।

मोदी-शाह के गुजरात ने फिर साबित किया-भाजपा का गढ़ है : रूपाणी

अहमदाबाद, (एजेंसी)। गुजरात के 6 नगर निगमों में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर महानगरों के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने भाजपा पर जो भरोसा किया है, वह व्यवर्थ नहीं जाएगा। साथ ही रूपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि गुजरात भाजपा का गढ़ है। 6 नगर निगमों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकास की राजनीति की विजय है। आनेवाले दिनों में नगर निगम के विकास में भाजपा सरकार को कसर नहीं छोड़ेगी। नगर निगमों के विकास की जिम्मेदारी जनता ने भाजपा को सौंप रखी है, जिसे वह अब तक बखूबी निभाती आई है और आगे भी निभाती रहेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि वर्षों से नगर निगमों में भाजपा को सत्ता की जिम्मेदारी सौंप कर गुजरात की जनता ने सत्ता विरोधी लहर शब्द गुजरात पर लागू नहीं होता है, इसका अध्ययन करने का राजनीतिक विश्लेषकों को संदेश दिया है। मतगणना से पहले विजय रूपाणी ने कल ही ट्वीट कर कहा था कि दिशाहीन और नेतृत्वहीन कांग्रेस इस बार महानगर पालिका चुनावों की स्पर्धा में थी ही नहीं।

भारत ने करोड़ों की संख्या में वैक्सीन करीब 70 देशों को दी : एस. जयशंकर

नई दिल्ली, (संवाददाता)। मोदी सरकार में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में भारत द्वारा किए जा रहे कई कार्यों की चर्चा की है। उन्होंने कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए कहा है कि दुनिया के देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत संकल्पबद्ध है।इसकारण बांग्लादेश से ब्राजील तक और मोरक्को से फिजी तक दुनिया की फामेर्सी कहे जाने वाले भारत ने करोड़ों की संख्या में वैक्सीन करीब 70 देशों को दी है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के तौर पर साथी देशों के साथ काम करने और आम सहमति बनाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए। इन मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक-दूसरे के आंतरिक मसलों का सम्मान भी किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया में मानवाधिकारों के सामने कई तरह चुनौतियां हैं। इनमें आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। लंबे समय से चला आ रहा आतंकवाद हो या फिर अन्य वैश्विनक अन्याय के विषय हो, कोरोना महामारी ने मानवाधिकारों की रक्षा की राह में और चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार परिषद के प्रति हमारा दृष्टिकोण बातचीत और सलाह की आत्मा वाला है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए सभी की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए बातचीत, सलाह और सहयोग अहम तरीके हैं। जयशंकर ने कहा है कि भारत के संविधान में मानवाधिकारों को मूलभूत अधिकारों के तौर पर जगह दी गई है। साथ ही नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। इसके अलावा सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की बात भी समाहित है।

अब कभी नहीं थमेगी दिल की धड़कन: मृतकों के दिल को मशीन से जिंदा कर 6 बच्चों में ट्रांसप्लांट किया, डॉक्टर बोले- नई तकनीक मील का पत्थर

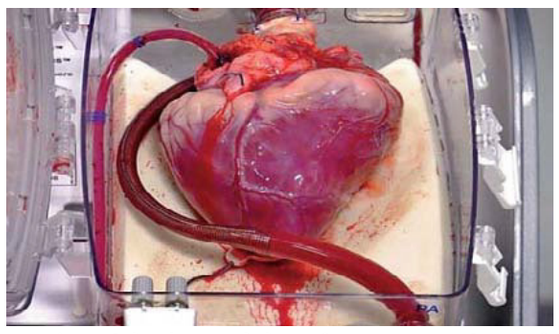

लंदन। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने पहली बार एक खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे दिल का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर लिया है, जो धड़कना बंद कर चुके थे। यानी वो मृत घोषित हो चुके व्यक्तियों के थे। अब तक 6 बच्चों में ऐसे दिल को ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। ये सभी बच्चे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। इससे पहले केवल उन व्यक्तियों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट होता था, जो ब्रेन डेड घोषित होते थे।

ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) के डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट की तकनीक में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। केंब्रिजशायर के रॉयल पेपवर्थ अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑर्गन केयर मशीन के जरिए मृत व्यक्तियों के दिल को जिंदा कर एक-दो नहीं, 6 बच्चों के शरीर में धड़कन पैदा कर दी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह दुनिया की पहली टीम बन गई है। एनएचएस के ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन विभाग के डायरेक्टर डॉ. जॉन फोर्सिथ ने कहा- 'हमारी यह तकनीक सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया में मील का पत्थर साबित होगी।

इस तकनीक से 12 से 16 साल के 6 ऐसे बच्चों को नया जीवन मिला, जो पिछले दो-तीन सालों से अंगदान के रूप में हार्ट मिलने का इंतजार कर रहे थे। यानी लोग अब मरणोपरांत ज्यादा हार्ट डोनेट कर सकेंगे। अब लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।'

एनएचएस के डॉक्टरों ने 'ऑर्गन केयर सिस्टम' मशीन बनाई है। मृत्यु की पुष्टि होते ही डोनर के दिल को तुरंत निकालकर इस मशीन में रखकर 12 घंटे तक जांचा जाता है और उसके बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। डोनर से मिले दिल को जिस मरीज के शरीर में लगाना है, उसके शरीर की आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन, पोषक तत्व और उसके ग्रुप का ब्लड इस मशीन में रखे दिल में 24 घंटों तक प्रवाहित किया जाता है।

पाकिस्तान में मस्जिद और मदरसों के संचालक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, पीएम पर वादाखिलाफी का आरोप

इस्लामाबाद। विपक्षी दलों के गठनबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के आंदोलन से पहले ही परेशान इमरान खान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है। देश की तमाम मस्जिदों और मदरसों के संचालकों ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। मस्जिदों और मदरसों के संचालकों का संगठन इमरान सरकार के नए वक्फ कानून का विरोध कर रहा है। उसका आरोप है कि इस कानून के जरिए सरकार मस्जिदों और मदरसों पर कब्जा करना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में मस्जिदों के उलेमाओं और मदरसा संचालकों के बीच बातचीत हुई। इसमें सरकार के नए कानून का विरोध किया गया। उलेमाओं का कहना है कि मजहबी मामलों में सरकार के दखलंदाजी वास्तव में इन पर कब्जे की साजिश है और इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। नाराजगी का आलम यह है कि इन संगठनों ने एक नया मोर्चा तैयार करने का फैसला कर दिया है और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी। संगठनों ने मौलाना जहूर अहमद अल्वी को अपना नेता चुना है।

डेटिंग एप के जरिए 55 लाख की लूट: दुबई में चार महिलाओं ने भारतीय को फर्जी मसाज सेंटर बुलाया, गर्दन पर चाकू रखकर रुपए ट्रांसफर कराए

दुबई । दुबई में चार अफ्रीकन महिलाओं ने एक भारतीय युवक को डेटिंग एप के जरिए फर्जी मसाज सेंटर बुलाया और चाकू की नोक पर उसके बैंक अकाउंट से 55,30,806 रुपए ट्रांसफर करा लिए। युवक के केस दर्ज करवाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। दुबई पुलिस ने मामले में तीन नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। चौथी महिला अभी फरार है। पूछताछ के दौरान पकड़ी गई एक महिला ने बताया कि उन्होंने टिंडर एप के जरिए उसे मसाज सर्विस देने के नाम पर फंसाया था। उसने युवक को बंधक बनाकर रुपए दुबई से बाहर ट्रांसफर करने और क्रेडिट कार्ड से निकालने की बात स्वीकार की है। दुबई की कोर्ट में केस की सुनवाई 4 मार्च को होगी।

युवक ने बताई पूरी घटना

पुलिस ने युवक का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, मीडिया से बातचीत में 33 साल के भारतीय युवक ने बताया कि, मैंने टिंडर एप के जरिए एक नंबर पर कॉन्टेक्ट कर मसाज करवाने के लिए बुकिंग की थी। इसके बाद मैं दुबई के अल रेफा रीजन में बने एक अपार्टमेंट में पहुंचा। यहां चार अफ्रीकन महिलाएं मिलीं। इन्होंने मुझे घेर लिया और मेरी गर्दन पर चाकू रखकर मोबाइल बैंक एप खोलने को कहा। मना किया तो मुझसे मारपीट भी की गई। उन्होंने मेरे अकाउंट से 55,30,806 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। उसके बाद मुझे उन लोगों ने छोड़ दिया। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और केस दर्ज कराया।

धरती बचाने के लिए धर्म की शरण में यूएन

धर्मगुरु बनेंगे इको योद्धा; धार्मिक संगठन दुनिया की चौथी इकोनॉमी, 10फीसदी जमीन इन्हीं के पास

न्यूयार्क। जलवायु परिवर्तन इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। अब यूनाइटेड नेशंस धरती को बचाने के लिए धर्म की शरण में आ गया है। यूएन एन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत 'फेथ फॉर अर्थ' अभियान शुरू किया गया है। इसका मकसद दुनियाभर के धार्मिक संगठन, धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं की मदद से 2030 तक धरती के 30त्न हिस्से को प्राकृतिक परिस्थिति में बदलने का लक्ष्य है।

इस कार्यक्रम के निदेशक डॉ. इयाद अबु मोगली कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बावजूद अभी तक दुनिया की ज्यादातर आबादी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं हो पाई है।

जलवायु परिवर्तन रोकने के तमाम प्रयासों के निष्कर्ष से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिर्फ धर्म में ही वह शक्ति है, जो दुनिया की बड़ी आबादी को पर्यावरण योद्धा बना सकता है।

डॉ. इयाद ये भी कहते है कि विज्ञान आंकड़े तो दे सकता है, मगर आस्था ही धरती बचाने का जुनून पैदा कर सकती है। डॉ. इयाद का मानना है कि विज्ञान और धार्मिक आस्था में ठीक वैसा ही संबंध हैं, जैसा ज्ञान और क्रियान्वयन में है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। यही 'फेथ फॉर अर्थ' अभियान शुरू करने के पीछे का मूल विचार है।

यह मूल विचार कैसे कैसे आया?

इस पर डॉ. इयाद बताते हैं कि 2017 में यूएन की बैठक में 193 देशों ने आने वाले दशक के लिए तीन लक्ष्य तय किए। पहला गरीबी हटाना, दूसरा सबको शिक्षा देना और तीसरा पर्यावरण बचाना। इस मंथन में यह बात निकली कि पर्यावरण बचाने में दुनियाभर के धार्मिक संगठनों का जितना योगदान मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा। इन संगठनों की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि दुनियाभर के 80त्न लोग धार्मिक नैतिकता का पालन करते हैं। यदि इन संगठनों की कुल संपत्ति जोड़ दी जाए तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। दुनिया की 10त्न रिहायशी जमीन इन संगठनों के पास है। 60त्न स्कूल और 50त्न अस्पताल धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। इस ताकत को मानव कल्याण के लिए मुख्यधारा में लाने की मंशा ने 'फेथ फॉर अर्थ' अभियान को जन्म दिया है।

इस साल जिनेवा की धर्म संसद में इको योद्धा भी पहुंचेंगे

इस मुहिम से पोप फ्रांसिस, शिया इस्माइली मुस्लिमों के इमाम 'इको योद्धा' बन चुके हैं। भारत में इस मुहिम के हेड अतुल बगई ने टिकाऊ भविष्य के लिए सद्गुरु, श्री श्री रविशंकर, शिवानी दीदी और राधानाथ स्वामी जैसे धर्म गुरुओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। डॉ. ईयाद कहते हैं कि इसी साल विश्व के धर्म गुरुओं की संसद जेनेवा में आयोजित होगी। इसमें धार्मिक इको योद्धा भी आएंगे। विज्ञान और धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता को जोड़कर इस अभियान को विस्तार देंगे।

सऊदी अरब आर्मी में महिलाएं शामिल होंगी

सेना ने 4 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी, शुरुआत में शहरों में तैनाती होगी

रियाद। सऊदी अरब में अब महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकेंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने करीब दो साल चले विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। शुरुआत में महिलाओं को चार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मंजूरी दी है। यह भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल, सिर्फ शहरों में इनकी तैनाती होगी और अभी इन्हें जंग के मैदान से दूर रखा जाएगा।

अब यूनिफाइड पोर्टल

'अरब न्यूज' की एक रिपोर्ट में कहा गया- डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक यूनिफाइड एडमिशन पोर्टल रविवार को शुरू कर दिया है। इसमें पहली बार पुरुषों के साथ ही महिलाओं को भी आवेदन की मंजूरी दी गई है।

फिलहाल, सैनिक से सार्जेंट के कुल 4 पदों के लिए महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। वे रॉयल सऊदी अरेबियन आर्मी, रॉयल सऊदी एयर फोर्स, रॉयल सऊदी नेवी, रॉयल सऊदी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स और रॉयल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के लिए

आवेदन कर सकेंगी।

शर्तें भी तय

सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड या मेडिकली अनफिट महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी। इनकी उम्र 21 से 41 साल के बीच होनी चाहिए। लंबाई 155 सेंटीमीटर जरूरी होगी। पहले से किसी सरकारी पद पर तैनात महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी। कम से कम हाईस्कूल की डिग्री होनी जरूरी है। विदेशी नागरिकता वाले व्यक्ति से शादी करने वाली महिलाएं भर्ती नहीं की जाएंगी।

प्रिंस सलमान की तारीफ

अरब न्यूज से बातचीत में कई महिलाओं ने प्रिंस सलमान और सेना के इस फैसले की तारीफ की। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशलिस्ट हलाह अल यानबावी ने कहा- 30 साल से इस मुद्दे पर विचार और बहस चल रही थी। लेकिन, आज प्रिंस सलमान ने तस्वीर बदल दी है। सरकारी नौकरी हो या सेना, अब सभी जगह महिलाएं नौकरी कर सकती हैं। हलाह ने आगे कहा- मेरे हिसाब से यह बहुत अहम फैसला है। हमारे समाज की सोच बदलने के लिए ऐसे ही कुछ और फैसले जरूरी हैं। आईटी एक्सपर्ट रहमा अल कायरी ने कहा- हमने अपने इतिहास में पहले कभी महिलाओं को जंग के मैदान में भेजने की बात तक नहीं सुनी थी। इस लिहाज से यह बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला है।

ये तीन हक महिलाओं को मिल चुके हैं

जून 2018 में महिलाओं को पहली बार कार चलाने की मंजूरी दी गई थी। वे स्टेडियम में फुटबॉल मैच देख सकती हैं और थिएटर भी जा सकती हैं।

वामपंथी रैपर पाब्लो हेजल गिरफ्तार:स्पेन में राजशाही के विरोध पर रैपर गिरफ्तार, देश में उपद्रव, समर्थन में पांच दिन से चल रहे प्रदर्शन और हिंसा भी

बार्सिलोना। स्पेन में एक रैपर की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसा और आगजनी शुरू हो गई है। पुलिस ने वामपंथी रैपर पाब्लो हेजल को राजशाही पर सवाल उठाने और गीतों में आतंकवाद का महिमामंडम के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उग्र-प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई शहरों में आगजनी हो रही है और लोग सार्वजनिक संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई स्टोर में लूटपाट तक की गई।

कुछ आतंकी तक कह रहे

इस रैपर को कई लोग गुंडा कहते हैं तो कुछ लोग तो इसे आतंकी बता रहे हैं। कुछ लोग इसे वामपंथी क्रांतिकारी कहते हैं। उसकी गिरफ्तारी के साथ ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी और आरोपों की संस्कृत खत्म करने की बहस छिड़ गई है।

10 साल चले गृहयुद्ध के जख्म भुला रहा सीरिया: मिसाइलों से इमारतें छलनी, लेकिन हौसलों के फौलाद से उम्मीदों के पंख

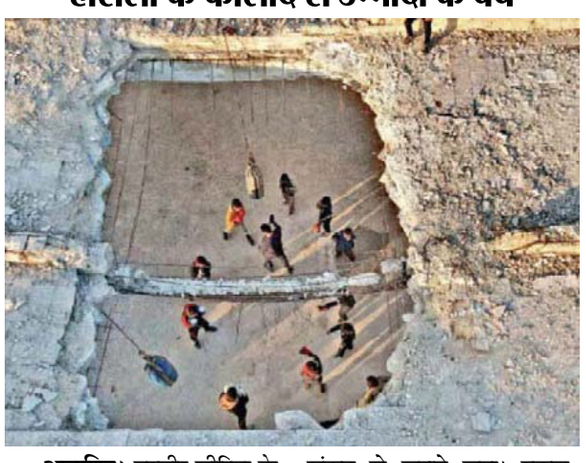

अतारिब। तस्वीर सीरिया के अतारिब की है। यहां बच्चे और युवा खंडहर में तब्दील इमारतों में उम्मीदों के पंख लगा रहे हैं ताकि अपने दिल-दिमाग से गृहयुद्ध की बुरी यादों को भुला सकें। दरअसल, अतारिब में रहने वाले 31 वर्षीय शिक्षक अहमद द्वार ने मिसाइलों के हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को बॉक्सिंग रिंग बना दिया है। यहां दिन भर में 100 से ज्यादा बच्चे बॉक्सिंग सीखने पहुंच रहे हैं।अहमद बताते हैं- 'सीरिया भी कभी गुलजार हुआ करता था। लेकिन गृहयुद्ध ने सब तबाह कर दिया। देश आर्थिक संकट से जूझने लगा। स्कूल-कॉलेज बंद हो गए। देश की आधी आबादी बेघर हो गई। सीरिया के बिगड़ते हालात बच्चों के दिमाग पर हावी न हों, इसलिए उन्हें बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया है ताकि उनकी बुरी यादों को भुलाकर उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार किया जा सके।' डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, गृहयुद्ध के कारण सीरिया में पिछले 10 साल में 3.80 लाख से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इनमें 22 हजार बच्चे और 13612 महिलाएं भी शामिल हैं।

कोरोना दुनिया में: अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा- अगले साल भी मास्क पहनना जरूरी हो सकता है, ब्रिटेन में वैक्सीनेशन तेज हुआ

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.19 करोड़ से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 77 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

2022 में भी मास्क जरूरी होगा: राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना टास्क फोर्स के अहम सदस्य और संक्रामक बीमारियों के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फौसी ने देशवासियों को सतर्क रहने को कहा है। एक प्रोग्राम के दौरान फौसी ने कहा- दुनिया में हुई कुल मौतों में से आधी हमारे देश में हुई। यह ऐतिहासिक विफलता है। हम इसे कभी याद नहीं करना चाहेंगे। अब भी वक्त है जब हम सतर्कता से काम करें। मेरा मानना है कि अमेरिकियों को अगले साल भी मास्क पहनना जरूरी होगा। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सतर्कता रखे बिना हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा पांच लाख के पार हो चुका है। फौसी ही बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं और डोनाल्ड ट्रम्प के दौर में भी वे इस पद को संभाल चुके हैं।

फौसी ने कहा- हालात इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वायरस के कितने और कैसे वैरिएंट सामने आते हैं। इसके अलावा यह भी देखना भी जरूरी होगा कि यह वैरिएंट कितने खतरनाक हैं। फिलहाल, हालात काबू किए जा सकते हैं और हम यही कर रहे हैं। मास्क एकमात्र ऐसी चीज है जिसके सही इस्तेमाल से हम भविष्य के खतरों को टाल सकते हैं।

ब्रिटेन में वैक्सीनेशन तेज

ब्रिटिश सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि देश में वैक्सीनेशन के लिए नई रणनीति बनाई गई है और अब इसी हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि जुलाई के आखिर तक देश के सभी वयस्कों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। इसके पहले यह लक्ष्य अगस्त और सितंबर के लिए तय किया गया था। साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन का विकल्प खुला रहेगा।

यूएन चीफ से सहमत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि उनके मुल्क में अगर सरप्लस वैक्सीन हुई तो वे इसे गरीब देशों को जरूर देंगे। जॉनसन का यह बयान अहम है। सिर्फ दो दिन पहले ह चीफ एंतोनिया गुटेरेस ने साफ कहा था कि अमीर देशों के पास वैक्सीन का जरूरत से ज्यादा स्टॉक मौजूद है और यह बाकी दुनिया खासकर गरीब देशों के लिए खतरे का संकेत है। इस बयान के डिप्लोमैटिक मायने भी हैं। रूस और चीन वैक्सीन डिप्लोमैसी के जरिए कुछ देशों में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तो गरीब अफ्रीकी देशों को टारगेट कर रहा है।

जॉनसन ने दोहराया कि गरीब देशों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। इस मीटिंग में जो बाइडेन भी मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कहा कि अमीर देशों को वैक्सीन स्टॉक का पांच फीसदी गरीब देशों को देना चाहिए।

इमरान सरकार की मुश्किल: पाकिस्तान के एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं, ब्लैक लिस्ट होने का भी खतरा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद ना के बराबर है। इसकी वजह यह है कि कुछ यूरोपीय देशों का मानना है कि इमरान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सभी कायदों को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। सोमवार से पेरिस में शुरू होने वाली वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान समेत कई देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर करने या उन्हें ब्लैक लिस्ट करने पर फैसला हो सकता है।

22 से 25 फरवरी तक पेरिस में बैठक होगी

पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' की वेवसाइट के मुताबिक FATF का फुल सेशन 22 से 25 फरवरी तक पेरिस में चलेगा, जिसमें पाकिस्तान सहित ग्रे लिस्ट के विभिन्न देशों के मामलों पर चर्चा होगी और अंत में इस पर फैसला किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में आयोजित मीटिंग में पाकिस्तान को फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया गया था।

आतंकी संगठनों को अब भी फंडिंग

रिपोर्ट के मुताबिक FATF के पास इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक जेयूडी और जैश के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तान की जमीन

से बेखौफ काम कर रहे हैं। अमेरिका ने भी पिछले दिनों कहा था कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने से रोकना होगा। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में दिक्कतें पाकिस्तान की वजह से ही बढ़ रही हैं।

फिलहाल ग्रे लिस्ट में

पाकिस्तान तीन साल से ग्रे लिस्ट में है। जून 2018 में उसे इस लिस्ट में रखा गया था। FATF ने उसे 23 पॉइंट का एक प्रोग्राम भी सौंपा था। संगठन ने कहा था कि न सिर्फ इन शर्तों को पूरा करना है बल्कि इनके पूरा होने के पुख्ता सबूत भी देने होंगे। इसके लिए पाकिस्तान को दिसंबर 2019 तक का समय दिया गया था। बाद में कोरोना की वजह से इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया था।

चेतावनी भी दी थी

FATF के प्रेसिडेंट मार्कस प्लीयर ने पिछले साल अक्टूबर की रिव्यू मीटिंग में कहा था- पाकिस्तान की कार्रवाई में बेहद गंभीर खामियां सामने आई हैं। हम उसे एक मौका और दे रहे हैं। इस बारे में फरवरी में विचार किया जाएगा। हम चाहते हैं कि कार्रवाई से पहले वहां की सरकार को एक मौका और दिया जाए। इसके बाद तय किया जाएगा कि क्या एक्शन लिया जाए। हम हमेशा राहत नहीं दे सकते। रिपोर्ट के मुताबिक FATF के पास कुछ इंटेलिजेंस वीडियो फुटेज मौजूद हैं, इनसे पता लगता है कि जमात और जैश के आतंकी सरगना अब भी पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रहे हैं। एक वीडियो अक्टूबर 2020 का है।

फंस जाएंगे इमरान

अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहता या ब्लैक लिस्ट होता है तो दोनों हालात में इमरान खान मुश्किल में आ जाएंगे। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को उनकी सरकार ठीक नहीं कर पाएगी और दुनिया का कोई भी संगठन उन्हें आर्थिक मदद नहीं दे सकेगा। घरेलू मोर्चे पर विपक्ष को उन्हें घेरने का एक मौका और मिल जाएगा। इमरान पहले से ही काफी दबाव में हैं और विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ सेना की मदद की वजह से वे सरकार चला रहे हैं।

प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार शाम तीन बजे से शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शाम तीन बजे से किया जा सकेगा। प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को 15 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। बता दें कि नीट की परीक्षा एक वर्ष में दो बार आयोजित होने किए जाने की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार, नीट 2021 पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीकरण प्रक्रिया में भाग लेने सकेंगे।

बता दें कि नीट 2021 परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (ह्रञ्ज) की तरफ से वर्ष में दो बार किया जाएगा। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो भारत के किसी भी संस्थान से मेडिकल या डेंटल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं।

इस परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को देश के विभिन्न मेडिकल और डेंटल संस्थानों के एमबीबीएस और बीडीएस जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल सकेगा। देश में मेडिकल क्षेत्र में अध्ययन की इच्छा रखने वाले सभी अभ्यर्थी के लिए नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बिना इसके किसी निजी या सरकारी संस्थान में दाखिला नहीं मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नीट परीक्षा के लिए किए गए बदलाव के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस साल की परीक्षा में छात्र नई उम्मीद कर सकते हैं। अब देखना होगा कोरोना काल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी छात्रों को किस प्रकार की राहत दे सकती है।

'कोरोना योद्धाओं के परिवारों को मिले ई-फूडकार्ट'

नई दिल्ली। दक्षिणी नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अभिषेक दत्त ने निगम की ई-फूडकार्ट योजना में कोरोना योद्धाओं के परिवारों को वरीयता देने की मांग की है। निगम ने ई-फूडकार्ट, फूड ट्रक एवं बस इत्यादि नए डिजाइन के रेस्टोरेंट तथा पार्कों में कियोस्क की दुकानों के स्थायी लाइसेंस देने के लिए योजना को मंजूरी दी है। ऐसे में निगम को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना से जान गंवाने वाले योद्धाओं के परिवार को इसमें रोजगार के लिए आवंटन करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अभिषेक दत्त ने कहा कि कोरोना संकट में निगम के कर्मियों के साथ ही पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों ने जान की परवाह किए बिना कार्य किया। इस दौरान इनमें से कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में इनके परिवार को सहयोग देने के लिए निगम को आगे आना चाहिए। साथ ही निगम की ई-फूडकार्ट योजना के तहत इन जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवारों को लाइसेंस देने चाहिए।

निगम में कांग्रेस दल के नेता ने कहा कि ऐसा करने से निगम कोरोना योद्धाओं को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेगा। उन्होंने यह कहा कि इस ई-फूडकार्ट के लिए लाइसेंस आवंटन में प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दत्त ने बताया कि उन्होंने निगम सचिव को प्रस्ताव दिया है कि महिला सुरक्षा के लिए निगम को चाहिए कि स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मकान मालिक की अनापत्ति लेकर उसकी दीवार पर लगाने की अनुमति दी जाए। दरअसल कोरोना काल के दौरान काफी संख्या में फ्रंट लाइन वर्कर्स को नुकसान हुआ, कई की तो जान भी चली गई। कई परिवार में कोरोना के फ्रंट लाइन वर्कर अकेले ही अपने घर में कमाने वाले थे, ऐसे लोगों की मौत के बाद अब परिवार में आर्थिक समस्या पैदा हो गई है। ऐसे लोगों की मदद के लिए ही उन्हें वरियता देने की मांग की गई है।

न्यू फ्रेंड कालोनी के फ्लैट से चोरी करने वाले नेपाली नागरिक समेत दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। न्यू फ्रेंड कालोनी थाना क्षेत्र में आठ फरवरी को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान नेपाल के रहने वाले पदम सिंह और झारखंड निवासी अब्जुल शेख के रूप में की गई है, जबकि इस चोरी के मामले में नेपाल मूल के तीन अन्य लोगों की पुलिस को तलाश है। इसमें पीड़ित के फ्लैट की इमारत का सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि आठ फरवरी को न्यू फ्रेंड कालोनी में रहने वाले शोभित जुनेजा ने पुलिस को शिकायत दी कि वे परिवार के साथ तीन फरवरी को दुबई गए थे, जहां से वह आठ फरवरी को वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में चोरी हुई है। शोभित ने पुलिस को बताया कि घर से पांच लाख रुपये और ज्वेलरी चोरी की गई है। एसएचओ सुमन कुमार की टीम ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की।

पुलिस की जांच में सामने आया कि जिस जगह चोरी हुई है, वहां का सुरक्षाकर्मी दो दिन पहले ही अपने पैतृक गांव नेपाल गया है। पुलिस ने सुरक्षाकर्मी दिनेश की काल डिटेल्स की जांच की, जिसमें पदम सिंह के नंबर पर कई बार बात की गई थी। पुलिस ने पदम सिंह के बारे में जानकारी जुटाई।

इसमें सामने आया कि वह नेपाल मूल का है और दिल्ली में विभिन्न कालोनियों में सुरक्षाकर्मी और खाना बनाने का काम करने वाले नेपाल मूल के लोगों के संपर्क में है। वे लोग पदम को घरों से बाहर जाने वाले लोगों की जानकारी देते थे। इसके आधार पर पदम और अब्जुल हवाई जहाज से दिल्ली आकर घरों की रेकी करते थे। रेकी करने के बाद आरोपित अपने गैंग के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस की मदद से पदम सिंह को दबोच लिया। इसके बाद अब्जुल को भी झारखंड से पकड़ लिया। दोनों ने चोरी के बाद नंबर बदल लिए थे।

दिल्ली में रसोई के कचरे से कैसे बनाएं खाद, आपके घर पर सिखाएगा नगर निगम

नई दिल्ली। रसोई से निकलने वाले सब्जियों के कचरे को कैसे खाद में तब्दील कर सकते हैं, यह जानकारी खुद नगर निगम के कर्मचारी आपके घर पर आकर देंगे। इसके लिए उत्तरी निगम की ओर से खाद बनाओ और पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। निगम की कोशिश गीले कचरे का निस्तारण करके न केवल लैंडफिल साइटों की ऊंचाई को कम करना है, बल्कि शहर की स्वच्छता रैंकिंग में भी बेहतर प्रदर्शन करना है। उत्तरी निगम ने इसकी शुरुआत करोलबाग जोन के नारायणा वार्ड से की है, जहां पर नारायणा की विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को निगम ने रसोई के कचरे से खाद बनाने की विधि बताई। नारायणा की आरडब्ल्यूए को निगम के उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने कार्यशाला के जरिये खाद बनाने की विधि को बताया। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे इस कचरे से बनने वाली खाद को अपने छत के पेड़ पौधों व पार्क के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि इसको लेकर निगम विभिन्न आरडब्ल्यूए से संपर्क कर रहा है। निगम ने कहा कि जो आरडब्ल्यूए उन्हें इस कार्यशाला के आयोजन की स्वीकृति देगा, निगम के कर्मचारी वहां जाकर पूरी विधि समझाएंगे।

उन्होंने बताया कि अभी 30 के करीब आरडब्ल्यूए ने इसको लेकर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि निगम कर्मी आरडब्ल्यूए के पास इसको लेकर संपर्क कर रहे हैं। नारायणा की कार्यशाला में निगम के उद्यान विभाग के अनुभाग अधिकारी रविंद्र गंगवार ने लोगों को बताया कि घर पर खाद बनाने की विधि बहुत आसान है। खाली डिब्बा लेकर उसमें छोटे छेद कर लें। फिर नीचे सूखे पत्तों को बारीक करके उसकी परत बना लें। रसोई से कटे हुए फल का कचरा या सब्जियों का जो भी कचरा निकलता है उसे इकट्ठा कर लें। फिर उस डिब्बे में डाल दें। उन्होंने कहा कि तीन-चार दिन का कचरा डालें और फिर उसके ऊपर सूखे पत्तों की परत बना लें। इससे 70-90 दिन में खाद तैयार हो जाएगी।

2 मार्च से बदलेगा दिल्ली-एनसीआर में मौसम, बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार सुबह लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ, लेकिन कोहरा नहीं था। वहीं, इससे पहले सोमवार को राजधानी दिल्ली में दिनभर गर्माहट का महसूस होती रही, लेकिन हवा की बढ़ी हुई रफ्तार से सुबह-शाम हल्की ठंड रही। मौसम विभाग के मुताबिक करीब एक सप्ताह ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सुबह-शाम हल्की ठंड रहेगी, जबकि दिन में गर्मी लगेगी। मार्च के पहले सप्ताह में मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 11 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 48 से 100 फीसद दर्ज हुआ। वहीं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 2 मार्च को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की संभावना बन रही है। इसके असर से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, जबकि हवा के रुख में बदलाव आएगा। इससे तापमान में गिरावट आएगी और कई दिन ठंड बनी रहेगी। वहीं, मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी में फिर से इजाफा होना शुरू हो जाएगा और यह फिर बना रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो होली के दिन 29 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में ठीकठाक गर्मी होगी। राजधानी दिल्ली में स्थानीय कारणों से प्रदूषण का लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एक्यूआइ 265, गाजियाबाद का 318, ग्रेटर नोएडा का 294, गुरुग्राम का 296 और नोएडा का 290 दर्ज किया गया। गाजियाबाद को छोड़कर सभी जगहों की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 245 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 2.5 का स्तर बढ़कर 131 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर का स्तर दर्ज किया गया।

दिल्ली पुलिस ने धरनास्थल खाली करने के लिए लगाए नोटिस, किसानों में रोष

दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और टिकरी बॉर्डर पर लगाये गए नोटिस के बाद किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से डॉ. दर्शनपाल ने बयान जारी करते हुए इन कार्रवाई को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर होने के बजाय मजबूत होता जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आये भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की।

पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बजाय किसानों को ही गिरफ्तार कर लिया। सरकार के किसान विरोधी साजिशों का हम कड़ा विरोध करते है। भाजपा द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की रोज कोशिशें की जा रही है। हम इसे सफल नहीं होने देंगे और किसानों का यह संघर्ष जरूर कामयाब होगा। टिकरी धरने पर दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें किसानों से धरनास्थल खाली करने की चेतावनी दी गयी है। इस तरह के पोस्टर अप्रांसगिक है, जहां किसान अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर दो माह से अधिक समय से किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की घोषणा के बाद किसानों ने दिल्ली में जिस तरह से उपद्रव किया था उसके बाद कुछ संगठन अलग हो गए थे। किसान नेता का कहना है कि हम पुलिस के इस कदम का विरोध करते हैं और किसानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें। इस तरह की धमकियां और चेतावनी से किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिशों का सख्त विरोध किया जाएगा व इससे किसान संघर्ष ओर मजबूत होगा।

भ्रष्टाचार के मामले में पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व उप निदेशक दोषी, कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

नई दिल्ली। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि यहां सभी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन जब बात लालच की आती है, तो वहां यह बात लागू नहीं होती। दोषी ने भी अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए बार-बार भ्रष्टाचार जैसा संगीन अपराध किया है। दोषी का लालच इससे भी साबित होता है कि वह पहले भी सात लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में सजा पा चुका है। राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश नीरजा भाटिया ने यह टिप्पणी पर्यावरण मंत्रालय के पूर्व उप निदेशक नीरज खत्री को भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल कठोर कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाते हुए की है। खत्री के अलावा वीवी मिनरल्स, इसके पार्टनर

एस. वैकुंडाराजन और लाइजन आफिसर शुभलक्ष्मी को भी सजा दी गई है। वैकुंडाराजन की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए तीन साल जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। वहीं, शुभलक्ष्मी की अकेली मां होने की दलील पर गौर करते हुए तीन साल जेल और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वीवी मिनरल्स पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। वैकुंडाराजन और शुभलक्ष्मी द्वारा जुर्माना अदा करने और फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की दलील के बाद 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई। वहीं, खत्री ने जुर्माना अदा नहीं किया, लिहाजा उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष अदालत ने कहा कि व्हाइट कालर क्राइम आम अपराध से भी खतरनाक है, क्योंकि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर चोट मारता है। यह अपराध पढ़े-लिखे और समाज में दबदबा रखने वाले लोगों द्वारा पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया जाता है। इससे समाज के आम लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तो भ्रष्टाचार को कैंसर और एड्स से भी गंभीर बीमारी की संज्ञा दे चुकी है। विशेष अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में आंखें मूंदकर नहीं बैठा जा सकता और इस मामले में तो कतई नहीं, क्योंकि दोषी नीरज खत्री ने अपने पद का इस्तेमाल निजी लालच की भूख मिटाने के लिए किया है। उसने यह भी नहीं समझा कि पर्यावरण संरक्षण कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ता है। विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र में सीबीआइ ने कहा था कि हरियाणा के रोहतक निवासी नीरज खत्री पर्यावरण मंत्रालय में 2012 में बतौर उप निदेशक तैनात थे। वीवी मिनरल्स तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एसईजेड स्थापित करना चाहती थी। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी, जबकि पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी नहीं मिली थी।

दर्द देने वालों को सजा तो दूर अब तक आरोप तक नहीं हो पाए तय

पूर्वी दिल्ली। दंगे का दर्द देने वाले किसी शख्स को अब तक गुनहगार साबित नहीं किया जा सका है। सजा तो दूर उन पर आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं। कोरोना के कारण लाकडाउन होने पर जांच से लेकर न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान के चलते आरोपितों को ये 'जीवनदान' मिला। कड़कड़डूमा की दो विशेष अदालतों में दंगे से जुड़ी सुनवाई चल रही हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि लाकडाउन न होता तो कई मामलों में अब तक आरोप तय हो जाते। हालांकि, लाकडाउन में ढील मिलने के बाद से न्यायपालिका ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाया। अब काफी मामलों में आरोप निर्धारण को लेकर बहस चल रही है। दंगे की साजिश को लेकर क्राइम ब्रांच में दर्ज प्राथमिकी संख्या 52 सबसे अहम है। जिसमें 18 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

अलगाववादी आसिया सहित तीन के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

नई दिल्ली। पाकिस्तान में अपने आकाओं के सहयोग से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों सोफी फहमीदा और नहीदा नसरीन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। पटियाला हाउस की विशेष अदालत में तीनों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल का सामना करने की दलील दी। इस पर विशेष अदालत ने देशद्रोह, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, देश के खिलाफ साजिश रचने और युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश में आरोप तय किए हैं। तीनों को एनआइए ने अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया था और तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। एनआइए की तरफ से दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि आसिया कश्मीर में अलगाववाद

आसिया पहले श्रीनगर की एक जेल में बंद थी। एनआइए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन लोगों के साथ-साथ उनके संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत के खिलाफ अप्रैल 2018 में जांच शुरू की थी।

को काफी बढ़ावा दे रही थी। आसिया के संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत के सदस्यों के पास से मिले मोबाइल फोन की जाच में पाया गया है कि वह पाकिस्तान के अपने आकाओं के लगातार संपर्क में थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और नहीदा नसरीन पर देश के खिलाफ कथित तौर पर जंग छेड़ने का आरोप है। अब तक की जाच में पाया गया है कि आरोपित आसिया, सोफी और नहीदा साजिश कर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थीं। आसिया और उसके सहयोगी साइबरस्पेस पर पाकिस्तान के समर्थन में अभियान चला रहे थे। उनकी तरफ से आतंकियों को भी मदद दी जा रही थी। 23 मार्च 2018 को जब संगठन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था तो आसिया ने अपने साथियों के साथ इस दिन को पाकिस्तान दिवस के तौर पर मनाया और पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान भी गाया था। आसिया पहले श्रीनगर की एक जेल में बंद थी। एनआइए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर उन लोगों के साथ-साथ उनके संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत के खिलाफ अप्रैल 2018 में जांच शुरू की थी। उनका संगठन गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है।

दंगे के आरोपित को मिली जमानत, मीडिया ट्रायल से ताहिर को राहत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगे के मामले में आरोपित राशिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि आरोपित आटो चालक है और जमानत मिलने पर उसके भागने का खतरा नहीं है। पीठ ने राशिद को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। याचिका के अनुसार राशिद को गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में दंगा फैलाने, आपराधिक साजिश, हत्या समेत अन्य धाराओं में मार्च 2020 में गिरफ्तार किया गया था। राशिद के अधिवक्ता ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष ने माना है कि काल डिटेल रिकार्ड के तहत याचिकाकर्ता की लोकेशन घटनास्थल के पास नहीं थी। उधर दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन की मीडिया ट्रायल से राहत की अर्जी पर कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रीवेंशन आफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ताहिर हुसैन और उसके साथी अमित गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें दोनों पर आरोप लगाया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन और दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए डमी कंपनियां बनाकर अवैध तरीके से 1.10 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस मामले में प्रसारित खबरों को लेकर ताहिर हुसैन ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उसने इससे राहत के लिए अर्जी लगाई थी।उसकी तरफ से अधिवक्ता रिजवान ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनी लांडिंग के मामले में सुनवाई आठ मार्च तक टल गई है। दंगे का मुख्य आरोपित व आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन जेल में न्यायिक हिरासत में है। उसके अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी दायर कर ताहिर से जेल में मिलने की इजाजत मांगी है। इस पर सुनवाई 26 मार्च को होगी।

प्रवासी पक्षियों को इस साल ज्यादा रास आई दिल्ली की आबोहवा

बाहरी दिल्ली। प्रवासी पक्षियों को इस साल दिल्ली की आबोहवा ज्यादा रास आई है। बीते साल की तुलना में राजधानी स्थित सातों बायोडायवर्सिटी पार्कों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में जहां 370 पक्षी पाए गए थे, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर 425 तक पहुंच गई है। यह तथ्य रविवार को बिग वर्ड डे के मौके पर राजधानी के सातों बायोडायवर्सिटी पार्कों में पक्षियों की गणना के बाद सामने आया है। दरअसल, 21 फरवरी को बिग वर्ड डे के मौके पर दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी पार्कों और पक्षी अभ्यारण्यों आदि में पक्षियों की गणना की जाती है।

ऐसे में दिल्ली स्थित यमुना, अरावली, तिलपथ वैली, कमला नेहरू रिज (नार्दर्न रिज), नीला हौज, तुगलकाबाद व कालिंदी बायोपार्कों में सुबह आठ बजे से दस बजे के बीच अलग अलग टीमों ने अनुमान के आधार पर पक्षियों की गणना की थी। गणना के बाद जो निष्कर्ष उभर कर सामने आए हैं, उससे साफ पता चलता है कि दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में पक्षियों के प्रवास के लिए पूरी तरह से अनुकूलित वातावरण है, जो प्रवासी पक्षियों की अपनी ओर खींचता है। यह गणना इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच शहरी परिवेश में करीब तीन हजार एकड़ में फैले सातों बायोडायवर्सिटी पार्क महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। गणना में प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण विविध प्रजातियां भी मिलीं। मसलन, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पाइड एवोसेट, अरावली में व्हाइट कैप्ड बंटिंग, नार्दन रिज में बूटेड इगल, कालिंदी में फेरूजिनस पोचार्ड जैसी प्रजातियां कलरव करती दिखाई दीं। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रभारी वैज्ञानिक डाक्टर फैयाज खुदसर ने बताया कि प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा की वजहों में कोरोना काल में लाकडाउन के दौरान वातावरण के प्राकृतिक स्वरूप में लौटना अहम कारण तो है, इसके अलावा दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क में पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भी अहम कारक हैं।

दो करोड़ रुपये की ठगी में सीपीआर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का निदेशक गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दो करोड़ रुपये की ठगी में सीपीआर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक पवन कुमार गर्ग (61) गिरफ्तार किया है।

आरोपित ने लोगों के शेयर और बांड अवैध तरीके से स्थानांतरित कर ठगी की थी। इसी तरह के अन्य मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर सेल भी कर रही है। ईओडब्ल्यू के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. ओ.पी. मिश्रा ने बताया कि आइपी एक्सटेंशन निवासी रविंदर गुप्ता ने पुलिस में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस को उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-10 में उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से सीपीसी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डीमैट

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पवन गर्ग ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रखी है। उसने वर्ष 1996 में अपनी कंपनी शुरू की थी। आरोपित ने अपने परिवार के सदस्यों को ही कंपनी में नियुक्त कर रखा है।

और ट्रेडिंग खाते खोले थे। शेयरों के कारोबार के दौरान कंपनी के निदेशक पवन गर्ग ने उनके भतीजों के साथ पहचान बनाई। बाद में उसने अवैध तरीके से उनके शेयर और बांडों को स्थानांतरित कर उनके रुपये हड़प लिए।

छानबीन करने पर पता चला कि पवन गर्ग ने उनके नाम से जाली डीमैट स्लिप भी तैयार की थी। उस स्लिप को उसने अवैध शेयर कारोबार के लिए स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया था। इसमें उन्हें 2.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि पवन गर्ग ने पीड़ित और उनके परिवार के नाम का शेयर और बांड को रुपये पाने के लिए गिरवी भी रखा था। यह रुपये शिकायतकर्ता के खातों में स्थानांतरित नहीं हुए थे। जबकि कंपनी के निदेशक को ऐसा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। ठगी का पता चलने पर डीसीपी मोहम्मद अली की टीम ने पवन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पवन गर्ग ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रखी है। उसने वर्ष 1996 में अपनी कंपनी शुरू की थी। आरोपित ने अपने परिवार के सदस्यों को ही कंपनी में नियुक्त कर रखा है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है।

संपादकीय

चबाने की क्षमता से बड़ा निवाला

मैंने पहले भी कहा है, अपने क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के लिए चीन काफी सावधानी से जांची-परखी रणनीति का इस्तेमाल करता है। इस दिशा में उसकी हर चाल सैन्य प्रतिक्रिया को आमंत्रित नहीं करती, लेकिन उसकी ऐसी कई छोटी-छोटी हरकतें मिलकर भौतिक बदलाव की वजह बनती हैं। कतरा-कतरा कुतरना एक बड़ा निवाला बन जाता है। हमने अपनी सरहदों पर यही देखा है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन ने कामयाबी के साथ इसी रणनीति को आजमाया है। पहले ट्रैक-2 बैठकों में उसके वार्ताकारों ने कहा था कि वे पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा नहीं करते हैं, उनका दावा सिर्फ कुछ द्वीपों और उनके आस-पास के पानी पर है। लेकिन जब उनसे नाइन-डैश लाइन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि यह गुओमिंदंग सरकार की विरासत है। यह याद करना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी प्रमुख झाउ एनलाई से कहा था कि चीनी मानचित्र भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से को चीनी हिस्से के रूप में दिखा रहे हैं, तब एनलाई ने कहा था कि ये पुराने गुओमिंदंग के दौर के मानचित्र हैं, जिन्हें अभी तक संशोधित नहीं किया गया है। ये दोनों दलीलें एक-सी नहीं लगती हैं? चीनी वार्ताकारों ने बाद में यह दावा करना शुरू कर दिया कि दक्षिण चीन सागर ऐतिहासिक जल है, जिस पर चीन के कुछ विरासती अधिकार थे, लेकिन वार्ताकार ने यह नहीं बताया कि ये अधिकार क्या थे? वे अभी भी यही कहते हैं कि चीन दक्षिण चीन सागर जल पर संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा नहीं करता है। एक बार जब इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आया, तब यह विवाद टिक नहीं सका। फिर भी दक्षिण चीन सागर में वास्तविक कब्जे, हड़पने और सैन्यीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वह अभी भी जारी है। कब्जे की इस ढुलमुल प्रक्रिया के किसी चरण में न तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पर्याप्त खतरा महसूस किया। अब जमीन पर बदले हुए तथ्यों को उलटने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, जो व्यावहारिक नहीं है।

यहां सबक यह है कि प्रारंभिक चरण में ही तेजी से जवाब देना चाहिए। इससे पहले की रणनीति के तहत नया मानचित्र तैयार हो जाए, फौरन कदम उठाए जाने चाहिए। भारत ने 2017 में डोका ला अभियान के साथ चीनी आक्रामकता के प्रति प्रतिक्रिया के अपने ढर्रे को बदल दिया था। इसमें कोई शक नहीं कि यह चीनी पक्ष के लिए एक आश्चर्य था। चीन की आक्रामक आधिकारिक प्रतिक्रिया और चीनी मीडिया में आई टिप्पणियों की बाढ़ में यही आश्चर्य जाहिर हुआ। वहां चीन की ओर से कुतरने की कार्रवाई की गई थी, जिसने भारत की ओर से अप्रत्याशित और चरित्र से परे असंतोष से भरी प्रतिक्रिया को बुलावा दिया। वह गतिरोध दो महीने से ज्यादा समय तक चला, लेकिन आखिरकार हल निकल ही आया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन हल निकालने की एक अहम वजह बना था। डोका ला के विपरीत पूर्वी लद्दाख में चीनी कार्रवाई कुतरने जैसी छोटी नहीं थी, यहां कार्रवाई बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती से समर्थित थी। इसका उद्देश्य चीन के फायदे के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) में ऐसा बड़ा बदलाव करना है, जिसे उलटना भारत के लिए जोखिम भरा और महंगा हो। जीवन की अभूतपूर्व हानि के साथ गलवान में झड़प अप्रत्याशित हो सकती है और संभव है, वह मूल रणनीति का जरूरी हिस्सा न हो। यही वजह है कि डोका ला की एक छोटी सी घटना की तुलना में गलवान पर चीनी पक्ष की प्रतिक्रिया लगभग मौन ही बनी हुई है। चीन की साजिश यह हो सकती है कि एलएसी पर अलग-अलग मान्यता वाले इलाकों को कब्जा लिया जाए और वहां भारतीय मौजूदगी व चौकसी को रोका जाए। उसकी कोशिश थी कि भारत को सरहद पर किसी भी फायदेमंद जगह से महरूम कर दिया जाए। चीन को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत सीमा विवाद के प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिक्रिया को सीमित नहीं रखेगा, बल्कि भारत में चीन के व्यावसायिक हितों पर हमला करने और अपने दूसरे भागीदारों के साथ खुद को अधिक करीबी से जोड़ने का काम करेगा। भारत ने सैन्य और आर्थिक, दोनों तरह के कदम उठाए। दक्षिण पैंगॉन्ग में ऊंचाइयों पर कब्जा किया और स्थाई रूप से 59 चीनी एप्स पर प्रतिबंध भी लगाया। इससे पहले भारत ने संकेत दिया था कि अगर रिश्ते पटरी पर लौटते हैं, तो प्रतिबंध हटाया भी जा सकता है। अब यह चीन के हाथ में है कि वह तनाव आगे बढ़ाता है या सीमा विवाद के साथ-साथ आपसी रिश्तों के अन्य पहलुओं को भी नुकसान से बचाता है।

अब क्या बीजिंग को शंघाई सहयोग संगठन से भारत को बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की भारत की सदस्यता के बारे में क्या करना चाहिए? क्या चीन को ब्रिक्स को भंग करने का नेतृत्व करना चाहिए, जो उसे रूस व अन्य सदस्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला सकता है? क्या उसे व्यावसायिक रूप से बदला लेना चाहिए, जो उसने अब तक नहीं किया है? दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें सैनिकों को सीमा से हटाने पर कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यह माना है। तथ्य यह भी है कि दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने को उपयोगी माना है, लेकिन यह प्रतीत होता है कि यह पहल चीन के पक्ष में नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि भारत-चीन संबंधों के अन्य पहलुओं को सीमा पर अशांति और शांति से अलग नहीं रखा जा सकता है। जबकि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जवाब दिया है कि सीमा की स्थिति को द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं के आड़े नहीं आने देना चाहिए, हालांकि चीन जानता है, यह मुमकिन नहीं है। चीन ने गलत कदम उठाया है और खुद को इससे कैसे निकालना है, वह नहीं जानता। क्या उसने इतना बड़ा निवाला काट लिया है, जितना वह चबा नहीं सकता?

प्रवीण कुमार सिंह

अपेक्षित समर्थन के अभाव में फिजियोथेरेपी जैसी प्रभावी प्रणाली का वांछित लाभ नहीं मिल सका

आजकल की भागमभाग भरी जीवन शैली में शारीरिक रुग्णता ने एलोपैथी दवाओं पर निर्भरता को अतिशय बढ़ाने का काम किया है। भौतिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने से इस समस्या का समाधान संभव है। भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी अनुप्रयोग भी व्यायाम और शारीरिक संचेतना पर आधारित हैं। मोदी सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और नर्सिंग सेक्टर की आधुनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अद्यतन बनाने के निर्णय लिए हैं तो भौतिक चिकित्सा को क्यों अनदेखा छोड़ दिया गया है? वह भी तब जब यह वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों स्तरों पर किफायती एवं प्रभावी प्रणाली है।

चिकित्सकों की कमी देश में एक प्रभावी स्वास्थ्य तंत्र की राह में बड़ी बाधा है। ऐसे में मोदी सरकार ने डेंटल और आयुष चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स के साथ एलोपैथिक परामर्श का रास्ता खोला है। हालांकि एलोपैथ लॉबी ने इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं देश में चिकित्सकों की उपलब्धता और आवश्यकता के आंकड़े बताते हैं कि आगामी दो दशकों में भी मानक उपलब्धता के आसार नहीं है। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने इस समस्या के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा की है। इसके अंतर्गत 'फिजियोथेरेपी' को उपचार की अहम प्रणाली के तौर पर अपनाने की बात है। फिलहाल देश में इस विधा का केंद्रीय नियामक संस्थान भी नहीं है। गत सप्ताह आए बजट में नर्सिंग के लिए नए मिडवाइफरी बिल का जिक्र तो हुआ, पर फिजियोथेरेपी को लेकर कोई उल्लेख नहीं हुआ जबकि देश में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी तक इसकी पढ़ाई कराई जाती है।

प्राक्कलन समिति ने फिजियोथेरेपी को एक पूर्णतः विकसित एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति के अनुसार फिजियोथेरेपी प्रामाणिक चिकित्सा प्रणाली है जिसका उपयोग पीडियाट्रिक्स से लेकर जेरियाट्रिक्स तक कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह कॉडियोवेस्कुलर रोग, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनेरी डिसीज (सीओपीडी), मधुमेह, ऑस्टोपायरोसिस, मोटापा और हाइपरटेंशन आदि के उपचार में अहम भूमिका निभा सकती है। समिति ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास फिजियोथेरेपी शिक्षा और

सार्वजनिक आरोग्य में इसकी भूमिका से जुड़ी कोई प्रामाणिक जानकारी ही नहीं है। समिति के अनुसार फिजियोथेरेपी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम प्रदान कर सकती है। समिति की राय है कि फिजियोथेरेपी को आर्थोपेडिक से विलग कर स्वतंत्र विषय के रूप में उभारना चाहिए। साथ ही प्रभावी फिजियोथेरेपी सेवाओं के लिए उपकरणों के अलावा उपचारात्मक प्रक्रिया के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता को समिति ने रेखांकित किया है। पहली बार किसी संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि अंग्रेजी दवाओं पर निर्भरता घटाने के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में फिजियोथेरेपी विकल्प अपनाने के अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि यह एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप आकार ले सके।

कुछ राज्यों में फिजियोथेरेपी के जरिये प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने पर कार्य शुरू हो गया है। इस दिशा में झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी परिषदों का गठन कर राज्य में उपलब्ध फिजियोथेरपिस्ट का उपयोग सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। हालांकि इसमें मेडिकल कमीशन या प्राकृतिक चिकित्सा कमीशन जैसी किसी केंद्रीय नियामक संस्था का अभी भी अभाव है। इस कारण यह आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं कि भारत में कितने ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध है और उनकी जन आरोग्य में क्या भूमिका है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में ऐसी परिषदों के गठन के लिए समय-समय पर आंदोलन होते रहते हैं। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी सामुदायिक चिकित्सा आधारित छह माह के एक विशिष्ट ब्रिज कोर्स के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थापना की अनुमति प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर फिजियोथेरपिस्ट को भौतिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वैसे भी फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में पुनर्वास विज्ञान के साथ-साथ एलोपैथिक चिकित्सा के अधिकांश विषय एमबीबीएस स्तर तक पढ़ाए जाते हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है।

भारत सरकार का कोई सांविधिक निकाय न होने के चलते भौतिक चिकित्सा की इस प्रभावशाली प्रणाली का वांछित लाभ नागरिकों को नही मिल पा रहा है। हालांकि छतीसगढ़, झारखंड और हरियाणा में बीते दिनों कानून बनाकर इस क्षेत्र को सरकारी नियमन के दायरे में लाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अखिल भारतीय स्तर पर एमएनसी या आयुष की तर्ज पर राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा आयोग की स्थापना भी की जानी चाहिए। नियामक तंत्र के अभाव में फर्जी भौतिक चिकित्सक भी देश भर में सक्रिय हैं। वैसे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हर जिले में राज्य सरकारों एवं एनजीओ के साथ मिलकर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र' संचालित किए जा रहे है। इनमें एक पद फिजियोथेरपिस्ट का भी होता है। हालांकि यह सुविधा जिला मुख्यालय पर ही है और यहां परामर्श भी केवल दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। बेहतर होगा छत्तीसगढ़ की तरह कस्बाई और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर भी स्वास्थ्य अधिकारी की तरह इनकी नियुक्तियों पर विचार किया जाए। वहीं केंद्र सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, रेलवे, खेल परिसरों, पीएसयू, ईएसआई, मेडिकल कॉलेजों के अलावा सभी बड़े निजी अस्पतालों में फिजियोथेरपिस्ट के पद रहते हैं जिनका वेतनमान द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के समान है।

आजकल की भागमभाग भरी जीवन शैली में शारीरिक रुग्णता ने एलोपैथी दवाओं पर निर्भरता को अतिशय बढ़ाने का काम किया है। भौतिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने से इस समस्या का समाधान संभव है। भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी अनुप्रयोग भी व्यायाम और शारीरिक संचेतना पर आधारित हैं। मोदी सरकार ने होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और नर्सिंग सेक्टर की आधुनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अद्यतन बनाने के निर्णय लिए हैं तो भौतिक चिकित्सा को क्यों अनदेखा छोड़ दिया गया है? वह भी तब जब यह वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों स्तरों पर किफायती एवं प्रभावी प्रणाली है।

ज्यादा बेल, कम जेल

आजकल हर किसी के अंदर हर किसी को जेल में डालने की प्रवृत्ति क्यों मजबूत होती जा रही है? सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया यह सवाल सभी संबंधित पक्षों के लिए गौर करने लायक है। कोर्ट के ध्यान में पिछले कुछ समय में आए ऐसे कई मामले थे जिनमें अभियोजन पक्ष बिना किसी ठोस आधार या जरूरत के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने या जमानत रद्द करने पर जोर दे रहा था। कोर्ट ने कहा कि न्यायशास्त्र के इस सिद्धांत को याद रखने की जरूरत है कि बेल (जमानत) नियम होना चाहिए और जेल अपवाद। इसी संदर्भ में दिल्ली की एक अदालत की यह टिप्पणी भी ध्यान देने लायक है कि राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता।

पिछले कुछ समय से राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करने में असाधारण तेजी देखी जा रही है। दिशा रवि और निकिता जैकब जैसे युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं का मामला तो है ही, कांग्रेस नेता शशि थरूर और छह जाने-माने पत्रकारों के खिलाफ दर्ज हुए मामले भी पुराने नहीं पड़े हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत ऐसे तमाम मामले भी याद किए जा सकते हैं जिनमें छोटी-छोटी बातों पर लोगों को गिरफ्तार करने, अनाप-शनाप धाराएं लगाने और जल्दी जमानत न मिलने देने की पुलिसिया प्रवृत्ति रेखांकित होती है।

कानून का शासन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आरोप लगने भर से किसी व्यक्ति को जेल भुगतनी पड़ जाए। सिद्धांत रूप में स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जघन्य अपराधों के अलावा शेष सभी मामलों में आरोपी को जेल में रखने की जरूरत तभी होनी चाहिए जब वह जांच में सहयोग न करे, उसके देश से बाहर भाग जाने का खतरा हो, या बाहर रहने पर उसके द्वारा सबूत मिटाए जाने का डर हो।

हाल के दिनों में ऐसे अनेक मामले देखने को मिले हैं जिनमें बेल को नियम और जेल को अपवाद मानने वाली इस न्यायिक परंपरा का सम्मान नहीं किया गया। इसके उलट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गईं।

समझना जरूरी है कि जमानत पर जोर देने वाले जुडिशल नॉर्म्स लोकतंत्र के लिए ऑक्सिजन की भूमिका निभाते हैं। इनके उल्लंघन को हल्के में लेने पर सख्त कानूनों का इस्तेमाल पुलिस-प्रशासन की मनमानी का सबब बन जाता है और अंततः ये राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने के औजार बन जाते हैं। कायदे से देखा जाए तो राज्य मशीनरी के इस अति-उत्साह पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन इस दिशा में कुछ करना तो दूर, उलटे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि सरकारों की इच्छा या मौन समर्थन से ही पुलिस अपने दायरे का विस्तार कर रही है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को उसकी हदें याद दिलाने की कोशिश की है। उम्मीद की जाए कि कम से कम अदालत के इस हस्तक्षेप के बाद सभी संबंधित पक्ष अपनी-अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करेंगे और उसे दुरुस्त करने में कोई हीलाहवाली नहीं दिखाएंगे।

नए संस्थान के समक्ष चुनौतियां, पुरानी गलतियों से सबक लेकर बढ़ें आगे

नए विकास वित्त संस्था यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआइ) को सार्थक बैलेंस शीट तैयार करने में समय भी लगेगा। इस कारण डीएफआइ निर्माण प्रक्रिया में सरकार को सतर्कता बरतने के साथ देश में वित्त पोषण की समस्या को दूर करने के लिए दीर्घकालिक नीतिगत बाधाओं को भी दूर करना होगा। आज डीएफआइ के निर्माण का आकर्षण इस बात में है कि यह अल्पावधि में भी लाभदायक साबित हो सकती है। ऐसे में 20 हजार करोड़ रुपये मूल्य बैलेंस शीट वाला संस्थान बनाना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती है इसके आकार को बड़ा करना। जब तक बैलेंस शीट कुछ लाख करोड़ रुपये की न हो, नया डीएफआइ अर्थव्यवस्था पर असर नहीं डाल पाएगा।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार से अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में व्यापक वृद्धि हुई। इसके बाद देश में फाइनेंसिंग को इक्विटी और डेट दोनों में क्षमता की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रतिभूति बाजार नियामक सेबी तथा स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी तथा क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसे निकायों की स्थापना ने इक्विटी बाजार को जबरदस्त लाभ पहुंचाया। लेकिन डेट मोर्चे पर इतनी प्रगति नहीं हुई, जिसका असर बुनियादी क्षेत्र की फंडिंग पर पड़ा और डीएफआइ जैसे संस्थानों की क्षमता पर भी। इसलिए डीएफआइ के लिए डेट फंडिंग के संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा।

हमारी अर्थव्यवस्था इस समय मंदी की चुनौती से जूझ रही है। ऐसे में व्यापक स्तर पर मांग में वृद्धि से ही अर्थव्यवस्था गतिशील होगी। डीएफआइ से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के हाथ में नकदी आएगी, लेकिन इसकी खुद धन जुटाने की क्षमता तय करेगी कि यह किस तरह का निवेश आकर्षित करने में सक्षम है। वास्तव में यह एनआइपी की तरह से परियोजना को धन उपलब्ध करा सका, तो देश में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ अर्थव्यवस्था भी गतिशील होगी।

अतीत में डीएफआइ का हमारा अनुभव भले ही अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अन्य विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने में डीएफआइ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी दर पर वित्त प्रदान करने की क्षमता रखता है। उचित दरों पर दीर्घावधि वित्त पोषण के मामले में डीएफआइ की सफलता कई कारकों से तय होगी। इन कारकों में सरकार द्वारा प्रभावी तरह से पूंजी डालने के लिए अतिरिक्त बजट संसाधनों को शामिल करना होगा। इसमें दीर्घावधि निवेशकों से संसाधन जुटाया जा सकता है। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है कि प्रस्तावित डीएफआइ का ढांचा किस तरह से तैयार किया जाता है, जिससे कि खास क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य आदि जरूरतें पूरी हो सकें।

अभी इस समय बैंक नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में आधारभूत संरचना के लिए दीर्घकालिक धन डीएफआइ से आ सकता है। लेकिन जब तक डीएफआइ की पहुंच फंड के सस्ते अंतरराष्ट्रीय स्नोत तक नहीं होगी, तब तक इसके भविष्य पर सवाल उठते रहेंगे। इस कारण सरकार को नियमों में ढील देकर विदेशी दीर्घावधि पूंजी प्रदाताओं को आकर्षित करना होगा। विकासशील देशों में आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए विकास वित्त संस्थान के प्रयोग सफल और लोकप्रिय रहे हैं, मगर जब भारत में इसकी चर्चा होती है तो अतीत के कड़वे अनुभव स्मृति पटल पर उभरने लगते हैं।

बाल यौन अपराध की घटनाओं के प्रति समाज और न्यायपालिका को संवेदनशील बनने की जरूरत

अधिनियम के तहत कड़ी सजा का प्रविधान महज इसलिए नहीं किया गया है कि यह मामला अवैध यौन हरकत का है, बल्कि इसलिए किया गया है, क्योंकि यह एक नाबालिग से ताल्लुक रखता है, जिस पर यौन हमले होने का खतरा अधिक रहता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जिसके आधार पर उसे पॉक्सो के तहत न्यूनतम तीन साल की सजा दी जा सके। लिहाजा अदालत उसे नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में आइपीसी की धारा 354ए के तहत एक साल की सजा बरकरार रखती है।

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न संबंधी एक मामले में फैसला सुनाया कि किसी नाबालिग के कपड़े उतारे बिना उसके वक्षस्थल को छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता। इस तरह की हरकत को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि किसी हरकत को यौन हमला माने जाने के लिए गंदी मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता।

इस फैसले ने कई संवेदनशील सवाल खड़े कर दिए हैं। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस विवादास्पद फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की और सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 27 जनवरी को इस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है और ऐसे में सब की निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिक गई हैं। शीर्ष अदालत ने उच्च अदालत के असंवेदनशील फैसले पर रोक लगाकर सही कदम उठाया, क्योंकि उच्च अदालत का यह फैसला दरअसल बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 की मंशा बाल संरक्षण के उलट है। दरअसल नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन हमले, यौन उत्पीड़न एक अति गंभीर संवेदनशील मामला है और इसी भावना को

समझते हुए इससे संबंधित कानून भी बनाए गए हैं। मगर कई मर्तबा अदालतें ठोस साक्ष्य नहीं होने की दलील आदि देकर आरोपी के प्रति अधिक कड़ा रुख अपनाने से गुरेज करती हैं। लिहाजा सर्वोच्च अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वह इस मामले पर विस्तार से चर्चा कर कानून व मानवीयता दोनों को ध्यान में रख एक नजीर पेश करेगी।

दरअसल यह मामला नागपुर में दिसंबर 2016 का है और आरोपी सतीश पर यह आरोप है कि वह 12 साल की नाबालिग लड़की को कुछ खिलाने के बहाने अपने घर ले गया था, जहां उसके वक्षस्थल को छुआ। पीड़ित बच्ची ने बताया कि 39 साल के सतीश ने उसके शरीर को छूने और निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी। पीड़ित बच्ची के इस बयान को अहम मानते हुए नागपुर की एक सत्र अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत तीन साल और आइपीसी के तहत एक साल की सजा सुनाई थी। आरोपी ने सत्र अदालत के इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की और उच्च अदालत ने सत्र अदालत के आदेश में संशोधन करते हुए दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत बरी कर दिया और आइपीसी की धारा 354 में एक साल की कैद बरकरार रखी। उच्च अदालत ने कहा कि यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध बनता है। लेकिन इसके साथ यह भी साफ कर दिया कि चूंकि व्यक्ति ने बच्ची के बदन से कपड़े हटाए बिना उसका स्पर्श किया था, इसलिए उसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है।

दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के इस फैसले से पॉक्सो एक्ट की मूल भावना को ही एक तरह से ठेस पहुंची है और इससे यही ध्वनित होता है कि कपड़ों के ऊपर से गलत मंशा से छूना कोई बड़ा अपराध नहीं है। आने वाले वक्त में क्या इस दलील का समाज में अपराधी प्रवृत्ति वाले बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या लड़की के बदन पर कपड़े होने की दलील का इस्तेमाल आरोपी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम नहीं करेगा? क्या यह सही है कि किसी नाबालिग को छूना केवल इसलिए वैध मान लिया जाएगा, क्योंकि त्वचा का त्वचा से संपर्क नहीं हुआ है। पूरे कपड़ों में क्या शोषण नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन व सूनी जगहों पर कपड़े पहने लड़कियों/ बच्चियों के साथ छेड़छाड़, वक्षस्थल को छूने सरीखी घटनाएं भी पॉक्सो के तहत अपराध नहीं मानी जा सकतीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी को कपड़े के ऊपर से छूना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमले की श्रेणी में नहीं आता।

बाल अधिकार संगठनों के कड़े संघर्ष के बाद बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 बनाया गया। यह अधिनियम यह स्वीकार करता है कि बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, लिहाजा जब पीड़ित कोई बच्चा हो तो उसके संरक्षण के लिए विशेष कदम, आइपीसी से परे कानून की जरूरत होती है। अधिनियम के तहत कड़ी सजा का प्रविधान महज इसलिए नहीं किया गया है कि यह मामला अवैध यौन हरकत का है, बल्कि इसलिए किया गया है, क्योंकि यह एक नाबालिग से ताल्लुक रखता है, जिस पर यौन हमले होने का खतरा अधिक रहता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जिसके आधार पर उसे पॉक्सो के तहत न्यूनतम तीन साल की सजा दी जा सके। लिहाजा अदालत उसे नाबालिग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के जुर्म में आइपीसी की धारा 354ए के तहत एक साल की सजा बरकरार रखती है।

बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न/ यौन हमले के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने की दर भी कम है। इसकी कई वजहों में एक तरफ अदालतों व उनसे संबंधित ढांचे, स्टाफ की कमी तो दूसरी तरफ पुलिस व न्यायपालिका में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को बाल पीड़ितों के साथ हमदर्दी से निपटने वाले प्रशिक्षण देने की कमी आदि हैं। उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत इस विवादास्पद फैसले के उस बिंदु की स्पष्ट व्याख्या कर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) 2012 को बल प्रदान करेगी।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की वापसी को लेकर हाईअलर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में कोरोना संक्रमण की तेजी से वापसी को लेकर कमर कस ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों को हाईअलर्ट पर कर दिया है।

देश में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब व हरियाणा सहित अन्य राज्यों में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हो गए हैं। टीम-11 के साथ करीब हर दिन समीक्षा बैठक करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की मंगलवार की समीक्षा बैठक में देश के कुछ राज्यों में फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते कोविद के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दिशा-निर्देशों के तहत रेड जोन से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य तौर पर परीक्षण कराने और क्वारंटीन रहने के लिए कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर प्रदेश में भी दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही इन सभी के अनिवार्य परीक्षण के साथ इनको क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक, डीएस नेगी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उत्तर प्रदेश में भले ही गिरावट आई है, लेकिन अब भी सभी जिलों में स्थिति की निगरानी की जा रही है। इसमें भी हमारा फोकस विशेष रूप से अन्य राज्यों की सीमा से लगने वाले जिलों पर है। इसके साथ ही सरकार अभी भी प्रत्येक दिन करीब एक लाख 25 हजार लोगों का कोविड टेस्ट करा रही है। हर जिले में कांटेट ट्रेसिंग भी की जा रही है। प्रदेश के हर जिलों की रोज रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक बार फिर से सभी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अन्य राज्यों में बढ़ते प्रसार के कारण प्रदेश के सभी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी नजर रखने और परीक्षण, ट्रैकिंग व उपचार जारी रखने का निर्देश दिया है। सरमार ने सभी जिलाधिकारियों को शिवरात्रि और होली सहित आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी जगह पर लोगों को इस दौरान भी फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रति जागरूक करने को कहा गया है। सरकार का सख्त निर्देश है कि प्रदेश में कहीं पर भी कोविड़ प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई ढिलाई न हो।

मुजफ्फरनगर में किसान व भाजपा के बीच हुए टकराव पर छिड़ा ट्विटर वार, संजीव बालियान बोले- यह रालोद की साजिश

मुजफ्फरनगर । सोरेम में हुए किसानों और भाजपा के बीच टकराव ने अब राजनैतिक रूप ले लिया है। रालोद के नेताओं ने ट्विटर पर भाजपा को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री ने इस पूरे मामले को रालोद की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहले से ही प्लानिंग की गई थी। इसमें से कोई खाप चौधरी या किसान नहीं थे बल्कि रालोद के ही पांच से छह नेताओं ने यह किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस घटना की पूरी जानकारी ट्वीट कर दी है। वहीं रालोद के नेता जयंत चौधरी ने भी इस मामले में भाजपा पर आरोप लगाया है।

केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने पूरे प्रकरण पर ट्वीट किया है। उनका कहना है कि रालोद ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। घटना के 10 मिनट के अंदर चुनाव लड़ने वाले रालोद नेता, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष गांवों में पहुंच गए। इससे साफ है कि घटना की साजिश रची थी। चुनाव में अभी समय है और एक साल बाद चुनाव में फिर आमने-सामने होंगे। समाज को बांटने का प्रयास न किया जाए। संवाद से विरोध कीजिए। बता दें कि रविवार को शामली के भैसवाल गांव में सपा ने माहौल खराब करने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोरम की घटना पर ट्वीट किया है। कहा कि बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष हुआ, कई लोग घायल हुए। भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो। किसान की इज्जत करो। कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे गांव वाले।

रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा आंदोलन को कुचलना चाहती है। ग्रामीणों से मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रालोद किसानों के साथ है। 26 को सोरम में महापंचायत होगी। पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने कहा कि ग्रामीणों के साथ मारपीट की जितनी निंदा की जाए कम है। भाजपा लगातार किसानों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। अब भाजपाई मारपीट पर भी उतारू हो गए हैं। इस प्रकार की गुंडागर्दी आज तक नहीं देखी। पूर्व विधायक राजपाल बालियान ने कहा कि सोरम की घटना से एक बार फिर साबित हो गया है कि भाजपा किसान विरोधी है। भाजपा के बड़े नेताओं को इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता है। इस दौरान पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, भाकियू के ब्लाक अध्यक्ष हरेंद्र मलिक, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

यूपी के सोनभद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने दिल्ली पहुंचे भिखारी बाबा

नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के सुदूर जिले सोनभद्र से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामूहिक विवाह में शामिल होने का न्योता देने भिखारी बाबा दिल्ली पहुंचे हैं। सामूहिक विवाह का यह कार्यक्रम सात जुलाई को सोनभद्र जिले के रामगढ़ नामक स्थान पर आयोजित होगा। भिखारी बाबा ने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड की 1001 गरीब व आदिवासी कन्याओं का विवाह समाज के सहयोग से कराया जाएगा।

रविवार रात ट्रेन के माध्यम से दिल्ली पहुंचने के साथ 27 बाबाओं का दल रामलीला मैदान स्थित हनुमान वाटिका से पैदल ही प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर निकला, लेकिन मिंटो ब्रिज के नजदीक दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया और न्योता लेकर कुछ साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल को पीएमओ ले गए। वहां अधिकारियों ने उनका न्योता ले लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली से बाहर होने का हवाला देते हुए उनसे मिलाने पर बेबसी जाहिर की। इस पर भिखारी बाबा ने कहा कि गरीब कन्याओं की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाह कार्यक्रम में शिरकत करके उन्हें आशीर्वाद दें। उन्हीं की अरज लेकर यहां पहुंचे हैं। भिखारी बाबा वर्ष 1982 से समाज के सहयोग से अब तक तीन हजार से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह करा चुके हैं।

बता दें कि भिखारी बाबा ने सोनभद्र जिले में अपना आशियाना रामगढ़ में बनाया है। उन्होंने वर्ष 2005 में यहां की गरीबी से द्रवित होकर निर्धन कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया था। इसके साथ ही अभियान शुरू हो गया। 18 अप्रैल 2005 को 21 कन्याओं के विवाह के साथ हुई शुरूआत आज बड़ा रूप ले चुका है। आश्रम में ही 2006 में बाबा ने लोगों के सहयोग से 151 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया। लोगों का साथ मिलता गया और कारवां बढ़ता जा रहा है।

वर्ष 2010 में रामगढ़ 101 तथा 2011 में अनपरा में 101 कन्याओं का विवाह कराया। इस वर्ष फरवरी माह में शिवद्वार में 101 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया। इसके अलावा मई में रामगढ़ आश्रम में तीन कन्याओं तथा इसके बाद नौगढ़ में 11 कन्याओं की शादी कराई। इसके अलावा वर्ष 2009 से रामगढ़ आश्रम पर अखंड हरिकीर्तन भी चल रहा है। लगातार निर्धन कन्याओं की शादी कराने से बाबा न सिर्फ सोनांचल, बल्कि जनपद में काफी प्रिय हो गए हैं। खुद तो नंगे पैर और गेरुआ वस्त्र पहन कर चलते हैं लेकिन भीख मांग कर निर्धन कन्याओं का विवाह भव्य तरीके से कराते हैं। दहेज रहित विवाह करा कर बाबा समाज में नई परंपरा भी कायम कर रहे हैं। यही कारण है कि भिखारी बाबा के पक्ष में आज तमाम लोग आ गए हैं।

विधान परिषद में सीएम योगी बोले- हजार करोड़ की लागत से होगा गांवों का विकास

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को प्रदेश का बजट जारी होने के बाद अब इस पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बजट सत्र में विधान परिषद में बजट पर भाषण दिया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में पेश बजट पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पांच लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपया के आकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बजट सबका साथ,सबका विकास और भरोसे के संकल्प के अनुरूप है। सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी बजट में समाज के सभी वर्ग, गांव, गरीब, किसान तथा युवा के हितों का भरपूर ख्याल रखा है। यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के लिए मील का पत्थर बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना के अंतर्गत इस बार हजार करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। गांवों के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। बजट में प्रदेश के गांवों में भी खेलकूद प्रोत्साहन के लिए भी व्यवस्था की गई है। गांव के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार बजट में गांव में ओपन जिम की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गांवों में खेल के मैदान के लिए जमीन भी आरक्षित की गई है। अब हजारों गांव में खेल के मैदान अलग से ही दिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की गतिविधियां बढ़ाने को लेकर हमारी सरकार बेहद गंभीर है। इसके साथ ही हर न्याय पंचायत स्तर पर गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसे हम स्थानीय एनजीओ के माध्यम से संचालित कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों के पुनरुद्धार व कल्याण की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस बार लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद विधान परिषद में प्रश्नकाल समाप्त हो गया। अब नियम 39 के तहत चर्चा शुरू होगी।

विधान सभा की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। इसके दौरान जौनपुर में युवक की पिटाई से मौत मामले पर काफी शोर-शराबा होने लगा। विपक्ष ने नियम 311 में मामला सुनने की मांग की।

कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों ने खोला छात्रा के बाहर निकलने का राज, बरामद हुए अधजले कपड़े

बरेली । शाहजहांपुर में छात्रा को सरेराह जलाकर मारने की कोशिश के मामले में देर रात एडीजी अविनाश चंद्र व आइजी राजेश कुमार पांडेय ने मौके पर पहुंच कर मुआयना किया। पुलिस को घटना स्थल पर छात्रा के अधजले कपड़े मिले है। वहीं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती छात्रा की हालत में कुछ सुधार है लेकिन अभी भी छात्रा चुप्पी साधे है।

कांट क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली छात्रा को उसके पिता सोमवार को दोपहर 11 बजकर 36 मिनट पर कॉलेज में छोड़ने गए थे। लेकिन देर शाम तक वह कॉलेज से बाहर नहीं निकली। शाम करीब छह बजे तिलहर थाना क्षेत्र के नगरिया मोड़ से रिंग रोड के पास छात्रा को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर देर रात एडीजी व आइजी ने मौका मुआयना किया।

एएसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी ने देर रात घटना स्थल के आस-पास जांच कराई कराई तो एक बाग में छात्रा के अधजले कपड़े मिले। हालांकि अन्य कुछ सामान मौके पर नहीं मिला है। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमे मुख्य गेट से छात्रा 11 बजकर 36 मिनट पर जाते दिखाई दी। इसके बाद 12 बजकर आठ मिनट पर पीछे के गेट से नहर पटरी होते हुए निकल गई। हालांकि इस बीच छात्रा के साथ कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को लेने के बाद उसके साथियों से पूछताछ की। छात्रा के पिता ने देर रात अज्ञात के खिलाफ केरोसिन डालकर जलाने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। घटना स्थल का देर रात तक मौका मुआयना किया गया है। कुछ साक्ष्य मिले है जिन पर पुलिस काम कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। छात्रा के साथियों से पूछताछ की जा रही है। प्रवीण सोलंकी, प्रभारी निरीक्षक

लखीमपुर में लापता चारों छात्राओं की सीतापुर में मिली लोकेशन, सीसी फुटेज में कपड़े चेंज करती आई नजर

लखीमपुर । शहर से सोमवार को संदिग्ध हालातों में लापता हुई एक इंटर कॉलेज की चार छात्राओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अलबत्ता पुलिस की छानबीन में अब तक यह जानकारी मिल पाई है कि चारों छात्राएं यहां से रोडवेज बस में सवार होकर सीतापुर तक पहुंची थीं। उसके बाद वह कहां गईं, इसका पता आभी नहीं चल पाया है। छात्राओं की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को आसपास के जिलों में एसपी विजय ढुल ने भेजा है।

यह है मामला – शहर के अलग-अलग मुहल्लों की रहने वाली चार छात्राएं यहां के एक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। इनमें तीन छात्राएं हाई स्कूल की और एक छात्रा इंटर की है। यह चारों आपस में सहेलियां भी बताई जा रही हैं। सोमवार सुबह चारों कॉलेज जाने के लिए घर से निकलीं, पर वहां पहुंची नहीं। दोपहर तक उनके न लौटने पर परिवारजन ने उनकी तलाश शुरू की। जब कहीं पता नहीं चला, तब देर शाम सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी।

इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने शहर में और आसपास के क्षेत्र में संभावित जगहों पर छात्राओं की तलाश शुरू करने के साथ ही कई जगहों के सीसी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। इसमें शहर के मुहल्ला थरवरनगंज में रेमंड शोरूम के पास लगे सीसी कैमरे में छात्राओं का फुटेज मिला है।

इसमें चारों छात्राएं पास में जेल की दीवार और एक बड़ी होर्डिंग की आड़ में कपड़े बदल कर वहां से जाती हुई दिख रही हैं। पुलिस की छानबीन में यह भी पता चला है कि चारों वहां से रोडवेज बस स्टैंड पहुंची और एक बस में बैठकर सीतापुर तक गईं। इसके बाद इन छात्राओं के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है। शहर कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि छात्राओं के बस में बैठकर सीतापुर तक पहुंचने की तस्दीक बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने भी की है। सीतापुर के आगे का इन छात्राओं का मूवमेंट नहीं पता चल पा रहा है।

चारों छात्राओं में दो छात्राएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जिनके घर वालों का कहना है कि वह अपने साथ 20-25 हजार की नकदी भी ले गई है। अन्य दो छात्राओं के पास कितने रुपये हैं, यह उनके परिवारजन नहीं बता पा रहे हैं। शहर कोतवाल का कहना है कि प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही छात्राओं का पता लगा लिया जाएगा। मामले में एसपी विजय ढुल ने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर में पुलिस की दो-दो टीमें लगी हैं। जल्दी छात्राओं को ढूंढ लिया जाएगा।

पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस सिलेंडर्स के लगातार बढ़ते दाम पर बिफरा विपक्ष,भाजपा पर बड़ा हमला

लखनऊ । देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को सरकार पर तंज कसा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध में ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार पर बड़ा वार किया है।

लखनऊ में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 26 पैसे बढ़ी है। इसके साथ ही डीजल की कीमत में 38 पैसे का इजाफा हुआ है। लखनऊ में अब पेट्रोल की कीमत 89.11 रुपया प्रति लीटर है जबकि डीजल 81.69 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसी तरह वाराणसी में भी पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़े हैं। वाराणसी में पेट्रोल के दाम 27 पैसे बढ़े हैं। जिसके कारण यहां पेट्रोल 89 रुपए 64 पैसे में एक लीटर मिलेगा।

पेट्रोल व डीजल की लगातार बढ़ती कीमत को लेकर बसपा मुखिया ने मंगलवार को दो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक ही अनवरत वृद्धि करके कोरोना प्रकोप, बेरोजगारी व महंगाई आदि से त्रस्त जनता को सताना सर्वथा गलत व अनुचित। इस जानलेवा कर वृद्धि के माध्यम से जनकल्याण के लिए धन जुटाए जाने का सरकार का तर्क कतई उचित नहीं है।

मायावती ने आगे लिखा कि केंद्र व राज्य सरकारें अगर पेट्रोल, डीजल आदि पर कर की लगातार मनमानी वृद्धि करके जनता की जेब पर जो भारी बोझ हर दिन डाल रही हैं उसे तत्काल रोका जाना बहुत ही जरूरी। वास्तव में यही सरकार का देश की करोड़ों गरीब, मेहनतकश जनता व मध्यम वर्ग पर बड़ा एहसान व भारी जनकल्याण होगा।

कटिहार में बड़ा सड़क हादसा; समस्तीपुर के एक ही परिवार के छह लोगों की मौत, पीएम मोदी, सीएम और डिप्टी सीएम ने जताई संवेदना

कटिहार । मंगलवार (23 फरवरी) की सुबह कटिहार जिले के एनएच 31 पर कुर्सेला थाना क्षेत्र में एक भीषण रोड हादसा हुआ। कोसी पुल पर एक स्कार्पियो व ट्रक की टक्कर हो गई। इस घटना में स्कॉर्पियो के चालक समेत छह लोगों की मौत हो गई। तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। सभी मृतक समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के रहने वाले थे और एक ही परिवार से संबंधित थे।

घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के कटिहार में हुई एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी उन्हें मिली है। पीएम ने मृतक के स्वजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। यहां बता दें कि कल भी कटिहार में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत और आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए थे। सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इसके अलावा कल कटिहार, खगडिया, सुपौल और भागलपुर में कई जगहों पर सड़क हादसे में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से कुछ लोग एक स्कार्पियो पर कटिहार आए थे। सभी एक शादी के रस्म में शामिल हुए। सभी लड़की पक्ष के लोग थे। इन लोगों ने कटिहार के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र स्थित फुलवरिया गांव एक लड़के के छेका किया। यहां से लौटने के दौरान मंगलवार की सुबह करीब छह बजे स्कार्पियो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस घटना में स्कार्पियो चालक समेत छह लोगों की मौत वहीं हो गई। तीन जख्मी हैं।

मृतकों में शिवजी महतो, नंदलाल महतो, राजकुमार, अजय महतो, रामस्वरुप साह एवं संतोष कुमार शामिल हैं। घायलों में कैलाश महतो, अर्जुन महतो व सुनील महतो का इलाज फिलहाल कुरसेला पीएचसी में चल रहा है। तीनों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने बताया कि प्रारंभिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों वाहन को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक और खलासी फरार हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मृतकों के स्वजनों को भी दी। सूचना पाकर स्वजन वहां पहुंचे।

बता दें कि सोमवार को भी एनएच 31 पर समेली के समीप ट्रक व आटो की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई। एन एच पर वाहनों की बेलगाम रफ्तार लगातार दुर्घटना का सबब बन रहा है। एनएच पर डिवाइडर नहीं होना भी घटना का एक अहम कारण माना जाता है।बिहार के मुख्यमंत्री नतीश कुमार ने कहा इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि घटना हृदय को झकझोर करने वाली है। लगातार सड़क हादसों में वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मृतक के स्वजन को अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों का समुचित इलाज कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार में दो दिनों में सड़क हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने इस घटना में दुख व्यक्त किया है। स्वजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने सभी से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें।

प्रश्न पत्र लीक मामले में केस दर्ज करने का निर्देश, स्नातक का पर्चा हुआ था लीक

भागलपुर । टीएमबीयू में स्नातक पार्ट थ्री गणित प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रभारी कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी ने केस दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। जांच कमेटी ने दो दिन पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रभारी कुलपति को सौंप दी थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए कहा गया है। प्रभारी कुलपति ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा वह जेल भेजा जाएगा।

विश्वविद्यालय सूत्रों की मानें तो प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच रिपोर्ट में पूर्व में निलंबित किए दो कर्मियों के अलावा परीक्षा विभाग के कर्मी और कॉलेज शिक्षक संदेह के घेरे में हैं। हालांकि रिपोर्ट में संदेह का आधार विरोधाभाषी बयान को बताया गया है। बयानों में मेल नहीं रहने के कारण संदेह जताया गया है।

सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि छठे पेपर और सातवें पेपर के सील पैकेट के साथ छेड़छाड़ हुई है। आठवें पेपर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। अब मामला पुलिस के पास जाने के बाद इस राज से पर्दा उठेगा कि आखिर प्रश्न पत्र लीक के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल हैं। लीक मामले में आरोपित कर्मियों का कहना है कि वे लोग कभी-कभी गोपनीय शाखा के बगल वाले कमरे में चाबी छिपाकर रख देते थे। ऐसे में किसी और की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। राजभवन के निर्देश पर टीएमबीयू ने आइटी सेल बनाया है। प्रभारी कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. निरंजन प्रसाद यादव ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आइटी सेल विश्वविद्यालय के कार्यों का डिजिटलाइजेशन करने का कार्य करेगा। इस सेल में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और यूडीसीए के प्रोफेसर इंचार्ज को संरक्षक बनाया गया है।

स्कार्पियो की बोनट पर सजाया पिस्टल, फिर बोले हैप्पी बर्थ डे टू यू

गोरखपुर । गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौडिया-कालेसर हाईवे पर दबंग युवकों को असलहे के साथ जन्मदिन मनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। स्कार्पियो की बोनट पर चार पिस्टल रखकर करीब दर्जन भर युवक जन्मदिन मनाते देखे जा रहे हैं। पुलिस इस फोटो को पुराना बता रही है। फिर भी इस मामले की जांच थानाध्यक्ष पीपीगंज को सौंप दी गई है।

एसओ को दी गई जांच की जिम्मेदारी

इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को भी कुछ युवकों ने असलहे के साथ फोटो वायरल किया है। युवाओं में अपनी धाक जमाने के लिए हाईवे पर दिन में ही उत्सव मनाते देखे जा रहे हैं। फोटो जंगल कौडिया-कालेसर हाईवे की है। बता दें कि अभी रविवार को भी बांसगांव थाना क्षेत्र से एक युवक ने रायफल के साथ अपनी वीडियो वायरल की थी। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी का कहना है कि यह फोटो संज्ञान में आई है। फोटो पुरानी बताई जा रही है। फिर भी पीपीगंज थानाध्यक्ष को घटना की जांच के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी खुलेआम सड़क पर असलहा लहराएगा तो गलत है। युवकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शहर में तीसरा मामला शनिवार का है। शहर के एक नेता पुत्र के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ मनबढ़ युवकों ने असलहों के साथ वाहनों का एक काफिला निकाला। बताया जाता है कि करीब 50 वाहनों पर सवार युवाओं का यह जत्था शहर के चंपा देवी पार्क से असलहा लहराते हुए निकला। इन युवकों ने फेसबुक पर इसकी वीडियो भी डाल रखी है। यहां से असलहे लहराते हुए यह युवक कुशीनगर पहुंचे। वहां पर विवाद व फायरिंग भी की है। वीडियो को पुलिस ने भी संज्ञान में लिया है। वह युवकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

बांसगांव थाना क्षेत्र के एक युवक ने हाथ में बंदूक लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। वीडियो में युवक अपने दोस्तो को भटौली में मिलने के लिए आमंत्रित कर रहा था। साथ ही यह भी कह रहा था कि गोली वहीं चलेगी। रविवार सुबह भटौली पहुंचकर पुलिस ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। छानबीन के दौरान पता चला कि युवक गीडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

वह एक रिटायर्ड दीवान की रायफल लेकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर रहा था। वह भटौली में अपने साथियों के साथ पहुंचा भी था, लेकिन पुलिस के आने से पूर्व भाग गया था। पुलिस ने रिटायर्ड दीवान को हिरासत में ले लिया है।

पंजाब में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद, लगभग 32 लाख गरीब परिवार होंगे प्रभावित

जालंधर । पंजाब में गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद कर दी गई है। इससे पंजाब के 32 लाख के करीब परिवार प्रभावित होंगे। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को निशुल्क राशन दिया जाता था। इस योजना को कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लाकडाउन/कर्फ्यू के चलते गरीब परिवारों को निशुल्क राशन देने के लिए शुरू किया गया था। योजना के तहत प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं तथा एक किलो दाल प्रति कार्ड जारी किया जाता था। वहीं, अब जरूरतमंद परिवार निशुल्क राशन लेने के लिए डिपो पर चक्कर काटने को विवश हो गए हैं।

कोरोना महामारी के कारण पंजाब में गरीब व दिहाड़ीदार परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप लेबर पंजाब के सभी जिलों से पलायन करके मूल घरों की तरफ लौट रही थी। इसे रोकने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरूआत की गई थी। बीते वर्ष अप्रैल माह में शुरू हुई इस योजना को बंद कर दिया गया है।

हालांकि, खाद्य व आपूर्ति विभाग की डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमारी के मुताबिक लाकडाउन के कारण ही यह योजना शुरू की गई थी, जो हालात सामान्य होने के बाद बंद कर दी गई है। वहीं, निशुल्क राशन हासिल करने वाले परिवारों की परेशानी बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए अलग से व्यवस्था बनाए जाने के बजाय इसे पंजाब में पहले से चलाई जा रही आटा-दाल स्कीम के तहत बनाए गए कार्डों पर ही लागू कर दिया गया था, जो कार्ड पंजाब सरकार के पोर्टल पर अपलोड किए गए थे, केवल उन्हीं कार्डों को इस योजना में शामिल किया गया था। इनकी संख्या 32 लाख के करीब है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति सदस्य पांच किलो गेहूं व एक किलो दाल प्रति कार्ड दी जाती थी।

मिसाल के तौर पर जिस कार्ड पर चार सदस्य दर्ज हैं। उस कार्ड पर बीस किलो गेहूं व एक किलो दाल प्रति माह के हिसाब से जारी किया जाता था। यह राशन डिपो होल्डर के मार्फत विभाग के इंस्पेक्टर की उपस्थित में वितरित किया जाता था।

एक नजर

कर्मचारियों की लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण की मांग

जबलपुर। मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति जिला शाखा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को अतिशीघ्र प्रदान करने, 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिए जाने, वेतन एवं योग्यता के अनुसार पदनाम देने सहित कर्मचारियों की लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रट पहुंचकर तहसीलदार रश्मि चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन, योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, मीनूकांत शर्मा, हेमंत ठाकरे, अनूप कुमार, अशोक परस्ते, दिनेश गौंड, गिरीशकांत मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।

महाराजा सोहेलदेव पासी की जाति बदलने का विरोध

जबलपुर। राष्ट्रीय पासी समाज महासंघ द्वारा अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा महापुरुष महाराजा सोहेलदेव पासी की जाति से छेड़छाड़ करके उन्हें दूसरी जाति में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसका पूरे देश में घोर निंदा करते हुए इसका विरोध किया जा रहा है। समाजसेवी चमन पासी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ अध्यक्ष डॉ. ऋषि बावरिया, श्यामसुंदर बावरिया, तोताराम पासी, प्रदीप पासी, पुनीत पासी, रोहित गूजर, विकास बावरिया, प्रकाश सोनी, सुनीत निग, रमा बावरिया, पिंकी बावरिया सहित बड़ी संख्या में पासी समाज के नागरिक मौजूद रहे।

रजक समाज का प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न

जबलपुर। संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी की जयंती पर अखिल भारतीय रजक महासंघ एबीआरएम के तत्वावधान में सदर रामलीला मैदान में रजक समाज के प्रांतीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। सह आयोजक संयुक्त रजक समाज कनौजिया पंच के सहयोग में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्यमंत्री शरद जैन, विधायक अशोक रोहाणी, विधायक विनय सक्सेना, विधायक सुशील तिवारी, अजय विश्नोई, आरएसएस प्रांत संचालक एड. प्रशांत सिंह, छावनी परिषद उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे की मौजूदगी में समाज के वरिष्ठजनों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर रजक महासंघ राष्ट्रीय संयोजक संदीप रजक, कनौजिया पंच अध्यक्ष ओमप्रकाश रजक, एड. रूपकमल रजक, रामपाल रजक, श्याम कनौजिया, कमलेश कनौजिया, राकेश कनौजिया सहित बड़ी संख्या में सामाजिकजन मौजूद रहे।

प्राचीन शिव कल्याण मंदिर में त्रिदिवसी आयोजन आज से

जबलपुर। प्राचीन शिव कल्याण मंदिर, जवाहरगंज में वरिष्ठ समाजसेवी सुरेश आहूजा की धर्मपत्नि स्व. गीता सोनी की स्मृति में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम-जानकी-हनुमान के मंदिर का निर्माण कराया गया है। राम दरबार प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना दिवस 23 फरवरी अपरांह 3 बजे से शोभायात्रा निकाली जाएगी। आयोजक सुरेश सोनी, समाज सेविका संगीता मनोज नामदेव, राधेश्याम साहू, पं. श्याम सुंदर त्रिपाठी, अजय अग्रवाल आदि ने बताया कि तीन दिवसीय आयोजन का 25 फरवरी को भंडारे के साथ समापन होगा।

पाटन नगर परिषद ने जगह जगह खोद डाली सड़क

पाटन। नगर परिषद पाटन द्वारा पूरे नगर में पाइप लाइनों का काम किया जा रहा है। इसके चलते नगर परिषद ने पाटन कमानिया से चौधरी मोहल्ला तक विभिन्न स्थानों पर नगर के बीचों बीच सड़क खोद दी है। इससे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीयजनों ने बताया कि जबकि कुछ दिन पहले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहां भी पाइप लाइन डाली जाएगी उनके लिए सड़क नहीं खोदी जाएगी लेकिन उनके आदेशो की अवहेलना की जा रही है। गड्ढे भी नहीं भरे जा रहे हैं।

पाटन में श्रीमद्भागवत कथा का छटवां दिन

पाटन। बजरंगढ़ में श्रीमद्भागवत कथा का सोमवार को छठवा दिन रहा। इस दौरान बाल विदुषी जया देवी ने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान विष्णु की कथा का गुणगान किया। पूरे ग्राम एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के भक्तगण पूरे भक्ति भाव से भाव विभोर होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। बजरंगढ़ के पंडित गोपी प्रसाद दुबे के मार्गदर्शन में बजरंगढ़ में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा आयोजन में बालमुकुंद सिंह, बलदेव सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पुलन्दर सिंह, रमेश सिंह, गोर सिंह, प्रेम सिंह, वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, शेष कुमार, शैलेन्द्र, अंशुल, दीपू, परम सिंह, राघवेंद्र सिंह, इमरत सिंह, वीरेंद्र सिंह एवं समस्त ग्रामवासियों का विशेष सहयोग मिल रहा है। कथा स्थल पर यजमान हीरा सिंह, भाई लाल यादव एवं मंडली के सदस्यगण मौजूद रहे।

प्रो. एडीएन बाजपेयी बिलासपुर यूनिवर्सिटी कुलपति नियुक्त

जबलपुर। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अरूण दिवाकर नाथ बाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति आदेश राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके द्वारा जारी किया गया। प्रो. बाजपेयी के कुलपति नियुक्त होने पर आरडीयू कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र, कुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्र, प्रो. कमलेश मिश्र, प्रो. धीरेन्द्र पाठक, डॉ. लोकेश श्रीवास्तव, डॉ. आर.के. गुप्ता सहित यूनिवर्सिटी के समस्त प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर जोधपुर में धारा 144 लागू, विद्यार्थियों को दी गयी छूट

जोधपुर । कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को भांपते हुए जोधपुर में एक बार फिर से निषेधाज्ञा लागू की गई है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के आंकलन के मद्देनजर गृह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने से पहले की रोकथाम के मद्देनजर ऐतिहातन ये कदम उठाया गया है।

जिसके तहत आयुक्तालय जोधपुर में धारा 144, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक्ट्ठा होने पर निषेधाज्ञा लागू की है।

आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठे नहीं होगे तथा सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाये रखेगें। निर्वाचन प्रक्रिया, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कक्षा 9 से 12 तक संचालित होनें वाले विद्यालय तथा महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाली परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।

स्वीमिंग पूल, सिनेमाहॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही खोले जा सकेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बडे सामुहिक आयोजन राज्य सरकार के आदेश, गाईडलाईन के अध्ययधीन ही अनुमत किए जा सकेगें। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 'नो मास्क नो एन्ट्री' की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। सार्वजनिक स्थलों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना निषिद्ध होगा।

आदेश के तहत वैवाहिक समारोह में विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा 'नो मास्क नो एन्ट्री की सख्ती से पालना की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकासी के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जाएंगा। सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि बार-बार सेनेटाईजर की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

वहीं अंतिम संस्कार, अन्त्येष्टि संबंधी कार्यक्रम में अनवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रेनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूदारा) पर राज्य सरकार के आदेश 27 अगस्त 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन की पूर्ण पालना की जायेगी। धार्मिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधानों के साथ सीमित संख्या में ही लोगों द्वारा प्रवेश किया जायगा। कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संबंधित अफवाह नहीं फैलायेगा तथा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार नहीं करेगा। समस्त सामुहिक गतिविधियों यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात ही आयोजित किए जा सकेंगे।

आपदा अधिनियम के तहत होगी कारवाही-यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा। धारा 144 के तहत जोधपुर में 5 से अधिक व्यक्तियों के एक जगह इक्ठे होने पर रोक रहेगी।

बीते 24 घंटे में नए केस में गिरावट, साढ़े 10 हजार मामले मिले व 13 हजार ठीक हुए

नई दिल्ली । महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान साढ़े 10 हजार मामले सामने आए हैं। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा रही। लगातार दो दिनों से 14 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 10 हजार 584 मामले सामने आए। इस दौरान 13 हजार 255 लोग ठीक हुए और 78 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान छह लाख 78 हजार 685 सैंपल टेस्ट हुए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल एक करोड़ 10 लाख 16 हजार 434 मामले सामने आए। इनमें सो एक करोड़ सात लाख 12 हजार 665 मरीज ठीक हो गए हैं। एक लाख 56 हजार 463 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस एक लाख 47 हजार 306 है। अब तक एक करोड़ 17 लाख 45 हजार 552 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसमें से 64,25,060 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें पहली खुराक मिली है। वहीं 11,15,542 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दूसरी खराक ले ली है। साथ ही 38,83,492 फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक दी गई है।

एक्टिव केस में गिरावट

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक्टिव केस में गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव केस 1.36 फीसद से गिरकर 1.34 फीसद हो गया है। रिकवरी रेट 97.24 फीसद हो गई है। डेथ रेट 1.42 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक 21 करोड़ 22 लाख 30 हाजर 431 सैंपल टेस्ट हो गए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 5210 मामले सामने आए। लागतार तीन दिनों से छह हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। राज्य में 19 फरवरी को 6,112, 20 फरवरी को 6,971 और 21 फरवरी को 6,971 मामले सामने आए। राज्य में अब तक कुल 21 लाख छह हजार से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं।

मॉडल प्राचार्य की वेदना से केंट विधायक को कराया अवगत

जबलपुर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने जारी विज्ञप्ति ने बताया कि पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती वीणा बाजपेई को अधिकारियों द्वारा अपने साथी अधिकारी को बचाने के लिए बिना कारण ही निलंबित करा दिया गया।

संघ प्रतिनिधिमंडल ने केंट विधायक अशोक रोहाणी को बताया गया उच्चाधिकारियों द्वारा एक कूट रचित साजिश के तहत मॉडल प्राचार्य द्वारा अधिकारियों का सहयोग न करने तथा आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निलंबित करा दिया गया, ताकि मॉडल प्राचार्य द्वारा की गई सही जांच पर लीपापोती कर आरपी चतुर्वेदी डीपीसी को बचाया जा सके। डीपीसी को बचाने के लिए मॉडल स्कूल प्राचार्य को निलंबित कराकर उनके विरुद्ध जांच पर प्रारंभ करा दी गई इस संबंध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कैंट विधायक अशोक रोहाणी से मिलकर महिला प्राचार्य की वेदना से विधायक को अवगत कराते हुए उनसे न्याय की गुहार लगाई गई । संघ के योगेंद्र दुबे , अर्वेंद्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, संजय यादव, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, बृजेश मिश्रा, दुर्गेश पांडे, एसपी बाथरे, वीरेंद्र चंदेल, मुकेश मिश्रा आदि ने विधायक अशोक रोहाणी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए महिला प्राचार्य के गलत निलंबन को निरस्त करने की मांग की।

पूर्व सांसद धनंजय महादिक के खिलाफ केस, बेटे की शादी में कोविड नियमों का हुआ उल्लंघन; पूर्व सीएम भी हुए थे शामिल

पुणे । महाराष्ट्र के पूर्व सांसद धनंजय महादिक और दो अन्य के खिलाफ पुणे में उनके बेटे के विवाह समारोह में 21 फरवरी को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है। इस समारोह में राकांपा प्रमुख शरद पवार, भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उपस्थित थे।

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं जिसे देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमरावती में सोमवार 22 फरवरी से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है तो पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। संक्रमण को देखते हुए पुणे के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इन सबके बावजूद शादी समरोह का इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया और इस दौरान किसी ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया हुआ था। सब लोग मास्क के बगैर ही घूमते नजर आये। कोविड नियमों के अनुसार विवाह समारोह में 200 मेहमानों की अनुमति दी गई है लेकिन यहां 700 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे।

सोमवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 5,210 नए मामले सामने आए और इससे एक दिन पहले रविवार को 7000 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। हालांकि मुंबई महानगर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में महामारी से किसी की भी मौत नहीं हुई।

स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। इससे पहले लगातार तीन दिन तक प्रतिदिन संक्रमण के छह हजार से अधिक मामले सामने आ रहे थे। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कुल मामले बढ़कर 2106094 हो गए।

शांति भंग करने, माहौल खराब करने वाले पर दर्ज हो एफआईआर

कांग्रेस नेताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

जबलपुर (एजेंसी)। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 20 फरवरी को महंगाई को लेकर आधा दिन मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। जिसके तहत कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता उपनगरी क्षेत्र रांझी में बंद के लिए आम जनता से संपर्क कर जन समर्थन जुटा रहे थे। उसी दौरान रांझी के एक दुकान संचालक द्वारा कांग्रेसजनों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कांग्रेस नेताओं पर झूठी शिकायत दर्ज कराई गई।

उपरोक्त शिकायत करते हुए कांग्रेसजनों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात चर्चा कर ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी समर्थक दुकानदार के खिलाफ जानबूझकर शांति भंग करने व वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज करते हुए माहौल खराब कर उपद्रव करने पर कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस की ओर से नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा, कांग्रेस नेता जगत बहादुर सिंह अन्नु, कांग्रेस नेता अभिषेक चौकसे, कांग्रेस नेता गोविंद यादव, प्रदेश महामंत्री रामदास यादव ने एसपी से मांग की है कि मामले की जांच कर दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर मुकेश राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष जगत मणि चतुर्वेदी, आजम अली खान, नेम सिंह, अनिल शर्मा, रमेश बोहित, लक्ष्मण समुद्रे, निर्मल जैन, राज कुमार सोनकर, जग्गू विश्वकर्मा, केके मिश्रा, नारायण गुप्ता, मनजीत सिंह, विनोद राठौर, गुलाब चौधरी, कन्हैया मराठा, आलोक भट्ट, सरबजीत नारंग, रवि राय, विष्णु बर्मन, संजय सिंह मरावी, दारा सिंह, बलराम चौधरी, सोनू दुबे, मामूर गुड्डू, शैलेश राठौर, पंकज पटेल, रंबल विश्वकर्मा, गंजू दुआ, रोहित यादव, प्रकाश उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे।

कोविड को लेकर चिंता जाहिर, वैक्सीन उत्पादकों ने कहा- नए वैरिएंट के मुताबिक बदल सकते हैं टीके

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने भारतीय दवा कंपनियों ने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि वो कोरोना वायरस के नए वैरिएंट से निपटने के लिए अपनी वैक्सीन में तत्काल बदलाव कर सकती हैं, अगर इसके आनुवंशिक अनुक्रम का पता चल जाता है। हाल के दिनों में भारत में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमित मामले पाए गए हैं। यह भी माना जा रहा है कि इन नए वैरिएंट के चलते ही महाराष्ट्र और केरल में मामले बढ़ रहे हैं। बायो-एशिया कांफ्रेंस में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की उप महानिदेशक निवेदिता गुप्ता ने कहा, जैसा कि हम देख रहे हैं नए मामले बढ़ रहे हैं, हम हॉटस्पॉट और क्लस्टर से नमूनें एकत्र कर रहे हैं और हम उनका अनुक्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा एल्ला ने कहा कि उनकी कंपनी आनुवंशिक अनुक्रम के लिए आइसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर निर्भर है और आंकड़े मिलते ही वह प्रभावी वैक्सीन बनाने में सक्षम है।

बता दें कि भारत अब कोरोना टीके की दूसरी खुराक के दौर में काफी आगे बढ़ चुका है, मगर कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता कम होती नहीं दिखाई देती। सरकार ने अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे पहले मुल्क के एक करोड़ हेल्थवर्कर्स व दो करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए रखा है। सरकार 50 साल से अधिक उम्र वाले व गंभीर बीमारियों से पीड़ित 27 करोड़ लोगों के लिए टीका लगवाने का अभियान अगले माह से शुरू करेगी।

अब तक देश में कोविड वैक्सीन कुल 1,14,24,094 लोगों को लगाई गई है। इसमें 75,40,602 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई हैं, जिसमें से पहली डोज 64,25,060 लाभार्थियों को दी गई है, दूसरी डोज 11,15,542 लाभार्थियों को दी गई है।

ट्रैक्टर रैली के बहाने सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा, आइएसआइ के गुर्गे ने जारी किया वीडियो

नई दिल्ली । भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचने की कोशिश में लगे पाकिस्तान का एक और नापाक चेहरा सामने आया है। कुख्यात खालिस्तानी नेता गोपाल सिंह चावला ने भारत में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के समर्थन के नाम पर पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली करने की बात कही है। चावला को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने काफी हिंसा की थी।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के गुर्गे चावला ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर ट्रैक्टर रैली की बात कही है। हालांकि, उसने कोई तारीख नहीं बताई है।

कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भांपते हुए ही भारत सरकार ने 17 फरवरी को एसजीपीसी की अगुआई में सिख जत्थे को पाकिस्तान में शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था।

दरअसल, किसान आंदोलन का कुछ आंतकी दल फायदा उठाने की फिराक में हैं, इसके संकेत सरकार देती रही है। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई, लाल किले पर जो उपद्रव मचाया गया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। किसान संगठन कह रहे हैं कि उनका हिंसा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर हिंसा किसके इशारे पर हुई ये सवाल खुफिया एजेंसी तलाशने में जुटी हुई हैं। अब पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली का एलान साफ इशारा करता है कि दिल्ली में हुई हिंसा के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं।

गौरतबल है कि कई किसान संगठन कृषि बिलों में विरोध में पिछले लगभग 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों की कई बार सरकार से भी बात हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति गठित कर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने की राह दिखाई है।

देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, इन शहरों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, मुंबई में 17 हजार लोगों का कटा चालान

भोपाल । देश में कोरोना महामारी फिर पैर पसारती नजर आ रही है। कई राज्यों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं हैं। ये बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। इस जानलेवा वायरस के प्रसार का मुख्य कारण लापरवाही ही नजर आ रहा है। इसलिए कई राज्य सरकार नियमों के प्रति फिर सख्त होती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नियम कड़े किए गए हैं। मुंबई में मास्क न लगाने पर 200 जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

मुंबई पुलिस ने बताया कि मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले तीन दिनों में ऐसे 17500 लोगों का चालान काटा गया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। वहीं, मुंबई की मेयर की सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करती नजर आ रही हैं। वह भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को फ्री में मास्क भी बांट रही हैं।

राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 294 केस सामने आए हैं, इनमें 104 मरीज़ इंदौर में और भोपाल में 76 पॉज़िटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने भोपाल और इंदौर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में कलेक्टरों से कहा कि थोड़ी-सी लापरवाही विकराल रूप ले सकती है, इसलिए सतर्कता बरतें।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को महाराष्ट्र से लगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। शिवरात्रि के पर्व पर प्रदेश में लगने वाले मेलों में सतर्कता बरतने के लिए भी कहा है। बैठक के दौरान बताया गया कि छिंदवाड़ा और बैतूल में लगने वाले मेलों में महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां सावधानी बरतना जरूरी है।

गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले हफ्ते से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे तेज वृद्धि महाराष्ट्र में देखने को मिली है। इसलिए महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन फिर लगाया गया है। वैसे बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन बड़ी तेजी से हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर जल्द विराम लग जाएगा।

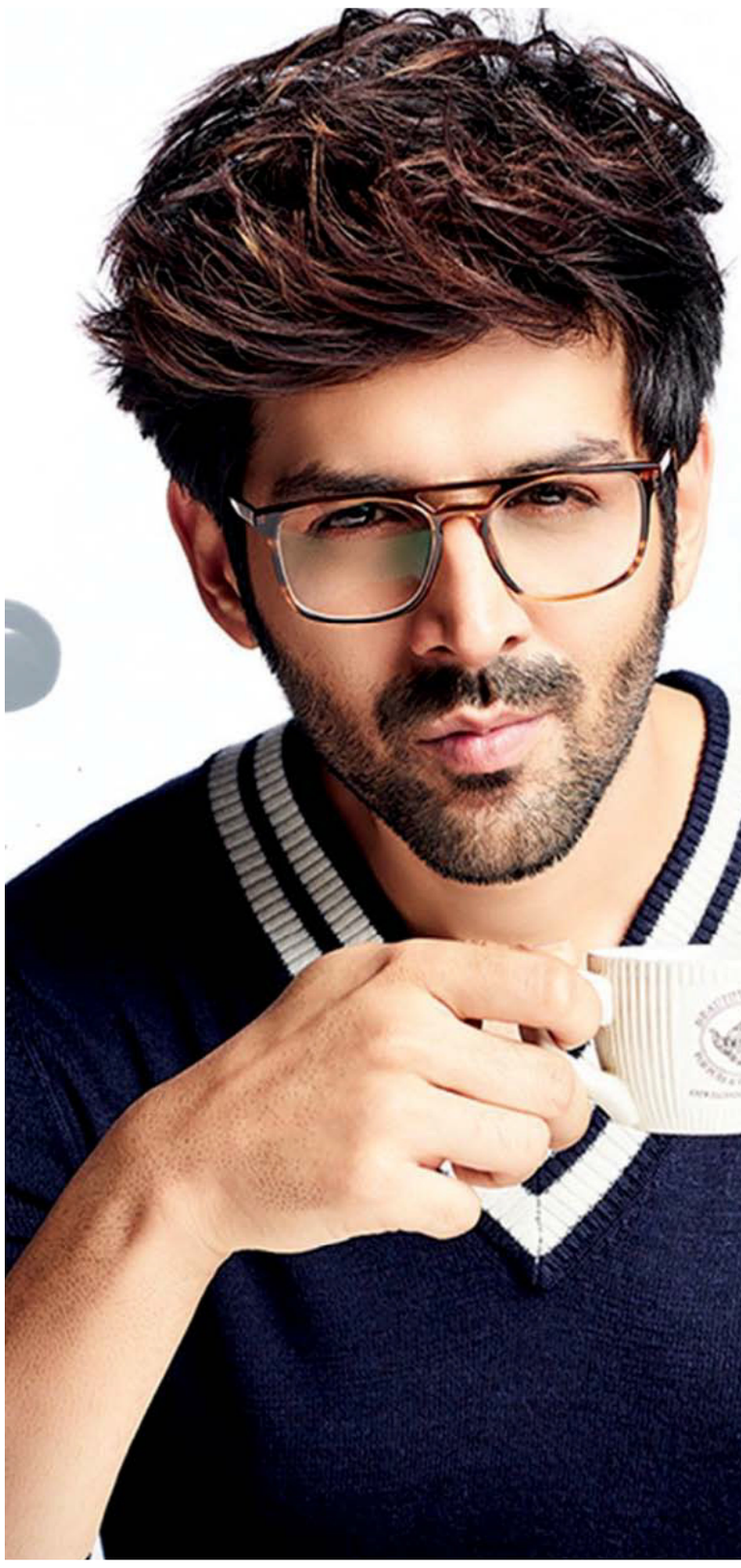

कार्तिक आर्यन ने बताया भूत-प्रेत आने के पीछे का सच

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन की आगामी मनोवैज्ञानिक-कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म भूल भुलैया 2, इसी साल 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्देशक अनीस बज्मी, निर्माता भूषण कुमार और मुराद खेतानी ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा अनोखे और डरावने अंदाज में की। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की टीम के साथ तस्वीरें शेयर की है जिसमें उन्होंने हाथों में कंकाल के सिर को पकड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरह कार्तिक आर्यन ने भी फिल्म का पोस्टर रिलीज किया जिसमें उन्होंने ने साधुओं वाले भगवा रंग का लिबास पहना हुआ है और हाथों में कंकाल की खोपड़ी पकड़ी हुई है। सूचना की घोषणा करते हुए आधिकारिक टी-सीरीज़ इंस्टाग्राम पर निर्माताओं ने लिखा, कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी अभिनीत सीट-ऑफ़-द-कॉम कॉमेडी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म भूल भुलैया 2 इसी साल 19 नवंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। भूषण कुमार, मुराद खेतानी द्वारा निर्मित, और टी-सीरीज़ और सिने 1 स्टूडियोज के बैनर तले कृष्ण कुमार, फ़िल्म का निर्देशन अनीस बज्मी द्वारा किया गया है और इसे फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने लिखा है।

वरुण धवन और कृति सेनन की 'भेड़िया' का टीजर आया सामने

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कृति सेनन की जोड़ी दिनेश विजान की हॉरर फिल्म 'भेड़िया' में नजर आने वाली है। 'स्त्री' और 'रूही' के बाद 'भेड़िया' दिनेश विजान के प्रोडक्शन हाउस की तीसरी हॉरर फिल्म होगी। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करने के साथ ही इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। टीजर वीडियो में दिखाया गया है कि घने जंगल में एक आदमी अचानक भेड़िया बन जाता है। माना जा रहा है कि इस भेड़िये के किरदार में वरुण धवन होंगे। कृति सेनन के किरदार के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। सोशल मीडिया पर टीजर को रिलीज करते हुए वरुण धवन ने लिखा, 'भेड़िया का प्रणाम स्त्री जी और रूही जी को।' टीजर में बताया गया है कि यह फिल्म 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। इस फिल्म को अमर कौशिक निर्देशित कर रहे हैं। यह एक हॉरर कॉमेडी होगी और फैंस इस अनाउंसमेंट के बाद काफी उत्साहित हैं। दिलवाले के बाद वरुण धवन और कृति सेनन की साथ में यह दूसरी फिल्म होगी। फिल्म में वरुण धवन और कृति सेनन के अलावा अभिषेक बनर्जी और दीपक डोबरियाल भी मुख्य भूमिकाओं में होंगे।

निक जोनस के साथ कभी गाना नहीं गाएंगी प्रियंका चोपड़ा

ऐक्टिंग के अलावा प्रियंका चोपड़ा सिंगिंग में भी हाथ आजमा चुकी हैं और उनके गाने काफी पसंद भी किए गए थे। हालांकि प्रियंका ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है कि वह कभी अपने पति निक जोनस के साथ गाना गाएंगी। इंटरनैशनल आइकन प्रियंका चोपड़ा ऐक्टिंग के अलावा म्यूजिक और सिंगिंग में भी अपना हुनर दिखा चुकी हैं। प्रियंका के गाने भी काफी पसंद किए गए थे। उनके पति निक जोनस दुनियाभर में मशहूर पॉप सिंगर हैं तो ऐसे में हमेशा ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कभी न कभी निक और प्रियंका की ऐल्बम आएगी। हालांकि प्रियंका ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है। प्रियंका से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि क्या वह निक के साथ मिलकर अपना यूजिक करियर बनाना चाहती हैं? इसके जवाब में प्रियंका ने कहा, 'क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह (निक जोनस) यूजिक के मामले में बेहतरीन हैं। मैं उनके साथ गाकर खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहती हूं। यूजिक के बारे में मैंने कुछ साल पहले सोचा था मगर अब उसके लिए टाइम नहीं है। मेरे पास पहले करने के लिए काफी काम हैं।' बता दें कि हाल में प्रियंका चोपड़ा ने अपने संस्मरणों को किताब के रूप में पेश किया है जिसका नाम 'अनफिनिश्ड' है। इस किताब में उन्होंने खुद से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बोली हैं जो अभी तक कम ही लोग जानते थे। अभी प्रियंका पिछले काफी दिनों से अपने पति निक के साथ लंदन में रह रही हैं। वहां पर प्रियंका अपनी आने वाली वेब सीरीज की शूटिंग कर रही हैं।

अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 18 जून को होगी रिलीज

बॉलीवुड अमिताभ बच्चन ने शुक्रवार को पुष्टि की कि उनकी आगामी फिल्म 'झुंड' 18 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित है। महानायक ट्वीट कर लिखा, ''कोरोना ने हमें झटका दिया। लेकिन अब वापसी का समय है! हम वापस आ गए हैं . झुंड 18 जून को रिलीज होने वाली है।' 'झुंड को नागराज मंजुले बना रहे हैं, जो इससे पहले सुपरहिट मराठी फिल्म सैराट बना चुके हैं। नागराज झुंड से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म फुटबॉलर अखिलेश पॉल के कोच विजय बारसे की जिंदगी पर आधारित है।

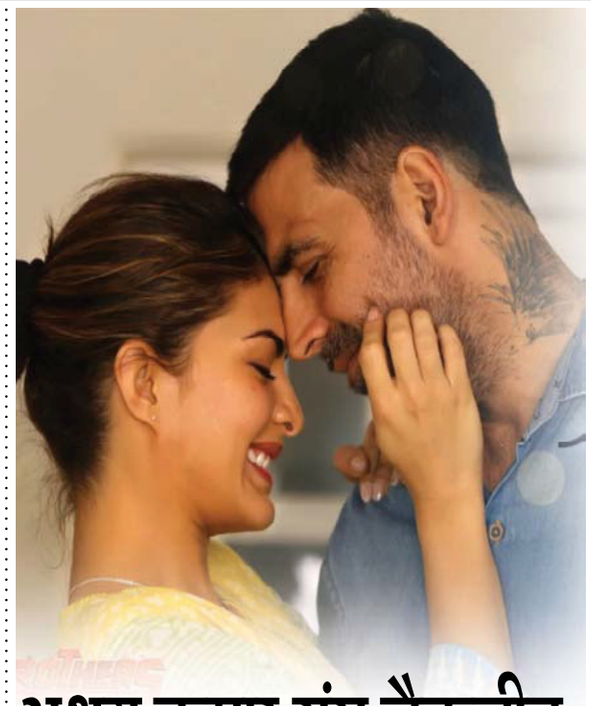

अक्षय कुमार संग जैकलीन फर्नांडीज का रोमांस!

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज जैसलमेर में अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की टीम में शामिल हो गई हैं। उन्होंने रेगिस्तान के लिए मशहूर शहर से भी तस्वीरें साझा कीं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज अब अक्षय कुमार की बच्चन पांडे की फिल्म का हिस्सा है और वह अब शूटिंग के लिए जैसलमेर में हैं। रेगिस्तान शहर से तस्वीरें शेयर करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जैकलीन ने ब्लैक एंड वाइट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा आज मैंने साजिदनाडियावाला की फिल्म बच्चन पांडे को ज्वाइंन किया। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ शूटिंग की शुरूआत। यह फिल्म 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के लिए काफी उत्सुक हूं। जैकलीन फर्नांडीज से पहले कृति सेनन और अरशद वारसी ने भी फिल्म के सेट से शूटिंग की तस्वीरें साझा की थी। कृति सेनन और अरशद वारसी ने अपने हिस्से की शूटिंग को पूरा कर लिया है। तस्वीर को शेयर करते हुए कृति सेनन ने लिखा सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार और यादगार शेड्यूल में से एक है। अरशद ने लिखा 卐बच्चन पांडे के शूट को पूरा किया। यह फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं कुछ सबसे प्रतिभाशाली और वास्तव में अद्भुत लोगों से मिला। कृति, जैकलीन, अक्षय, साजिद, फरहाद और निश्चित रूप से चालक दल।।आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार को एक गैंगस्टर के रूप में देखा जाएगा।

डिजिटल डेयू करने जा रहे शाहिद कपूर

मौजूदा परिस्थितियों में कई बॉलीवुड सितारों ने ने डिजिटल ह्रश्वलेटफॉर्म के ह्रश्वाति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। वेब सीरीज के साथ-साथ फिल्में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा रही हैं। शाहिद कपूर के डिजिटल डेब्यू को लेकर काफी वत से खबरें आ रही थी। अब यह कंफर्म हो गया है कि शाहिद कपूर, राज और डीके की वेब सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस सीरीज की घोषणा कर दी है। हालांकि, इसका शीर्षक अभी निर्धारित नहीं है। यह एक थ्रिलर सीरीज होगी, जिसे राज निदिमोरू और कृष्णा डीके द्वारा बनाया जाएगा। खबरों के अनुसार शाहिद ने कहा, मैं काफी समय से राज और डीके के साथ काम करने का इच्छुक था। जब से मुझे इसकी कहानी पसंद आई, तभी से मैं काफी उत्साहित हूं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मेरा पसंदीदा भारतीय शो 'द फैमिली मैन' है। मैं अपने डिजिटल डेयू के लिए इस प्रोजेट से बेहतर नहीं सोच सकता। बता दें कि 'द फैमिली मैन' को भी राज और डीके ने निर्देशित किया है। निर्माता राज और डीके ने कहा, हमारा उद्देश्य हमेशा हर फिल्म या सीरीज के साथ बेहतर काम करना रहा है। यह हमारा पसंदीदा स्क्रिप्ट है और शाहिद इसके लिए परफेट हैं। वह हमेशा इस सीरीज के लिए हमारी पहली पसंद थे। उन्होंने कहा, शाहिद एक रोमांचकारी अभिनेता हैं। वे अमेजन प्राइम वीडियो के हर सीरीज के प्रति अधिक जिमेदार महसूस करते हैं। यह शानदार पार्टनर रहा है और वे सीरीज को बनाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। सीरीज की कास्टिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस प्रोजेट के निर्माता जल्द ही सीरीज की कास्टिंग से संबंधित घोषणा कर सकते हैं।

मोटेरा में एक साथ कई रिकार्ड बना सकते हैं विराट

अहमदाबाद, (एजेंसी)। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बुधवार से यहां मेहमान टीम इंग्लैंड के साथ होने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एकसाथ कई रिकार्ड बना सकते हैं। तीसरा मुकाबला बुधवार से अहमदाबाद के नए बने मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। दिन-रात्रि का यह पहला मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। विराट इस मैच में कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर कई रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर टीम इंडिया मोटेरा टेस्ट जीत लेती है तो कोहली की कप्तानी में अपनी धरती पर यह भारतीय टीम की 22वीं टेस्ट जीत होगी। इसी के साथ ही विराट कप्तान के तौर पर महेन्द्र सिंह धोनी के सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने के रिकार्ड को पीछे छोड़ देंगे।

विराट और धोनी बतौर कप्तान देश में 21-21 टेस्ट जीतकर अभी बराबरी पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में हुआ दूसरा टेस्ट जीतने के बाद विराट ने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ऐसे में मोटेरा में उनके पास धोनी को पीछे छोड़कर देश का सबसे सफल टेस्ट कप्तान बनने का मौका होगा। वहीं,

अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो कोहली पहले ही सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन गये हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 58 टेस्ट में से 34 जीते हैं जबकि 14 मैच हारे और 10 ड्रॉ रहे हैं। उधर, धोनी की कप्तानी में भारत ने 60 टेस्ट खेले थे। इसमें टीम को 27 में जीत और 18 में हार मिली थी जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे थे।

इसके अलावा, बतौर कप्तान वे एक और खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। अगर कोहली इंग्लैंड के खिलाफ गुलाबी गेंद से होने वाले टेस्ट में शतक लगाने में कामयाब होते हैं। तो वह ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक मारने का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यह कोहली का बतौर कप्तान 42वां अंतरराष्ट्रीय शतक होगा। अभी पोंटिंग और कोहली के 41-41 शतक हैं। पोंटिंग ने 41 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के लिए 324 मैच खेले जबकि विराट ने 190 मैच में 41 शतक लगाए हैं। वहीं इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ तीसरे नंबर पर हैं।उन्होंने बतौर कप्तान 286 अंतरराष्ट्रीय मैचों मैच में 33 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने बतौर कप्तान 93 अंतरराष्ट्रीय मैच में 20 शतक लगाए हैं.

इसके अलावा कोहली के पास घर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठा बल्लेबाज बनने का मौका भी है। कोहली के अभी घर में 41 टेस्ट में 66 की औसत से 3703 रन हैं। घर में ओवरऑल टेस्ट रन बनाने के मामले में कोहली अभी सातवें नंबर पर हैं। दिलीप वेंगसरकर 3725 रन के साथ छठे और वीवीएस लक्ष्मण 3767 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं। यानी लक्ष्मण को पीछे छोड़ने के लिए कोहली को सिर्फ 65 रन और बनाने हैं। वेंगसरकर ने घर में 54 जबकि लक्ष्मण ने 57 मुकाबले खेले हैं।

वहीं, भारतीय कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ घर में टेस्ट में एक हजार रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन सकते हैं। अभी वे इससे 12 रन पीछे हैं। सुनील गावस्कर(1331) और गुंडप्पा विश्वनाथ(1022) ऐसा कर चुके हैं। मोटेरा में कोहली विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में भी एक हजार रन पूरे कर सकते हैं। फिलहाल, उनके डब्ल्यूटीसी के 12 मैच में 850 रन हैं। भारत की तरफ से सिर्फ अजिंक्य रहाणे भी एक हजार से ज्यादा रन बना सके हैं।

मियामी में फोटो के लिए पोज देते हुए मुक्केबाज साउल और एवीनी।

चेपॉक जैसी ही होगी मोटेरा पिच : एंडरसन

अहमदाबाद, (एजेंसी)। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडसरन का मानना है कि नवनिर्मित मोटेरा स्टेडियम की पिच भी चेन्नई के चेपक मैदान की पिच के समान ही रहेगी। एंडसरन के अनुसार इस पिच पर अभी हरी घास दिख रही है पर उन्हें पूरा विश्वास है कि दिन रात्रि टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले तक उसे काट दिया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच बुधवार से क्रत्रिम रोशनी में खेला जाएगा। इंग्लैंड को चेपक में हुए दूसरे टेस्ट में 317 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। एंडरसन ने कहा, पिच पर अभी घास है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे तो पिच पर यह घास नहीं होगी। उन्होंने कहा, इसलिए हमें अभी टीम की घोषणा के लिए इंतजार करना होगा। एक तेज गेंदबाज होने के नाते हमें हर तरह के हालातों को देखते हुए अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर स्विंग मिलता है तो यह शानदार होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें तब भी अपनी प्रभावी भूमिका निभानी होगी। एंडरसन ने कहा कि उन्होंने गुलाबी एसजी गेंद से नेट सत्र के दौरान गेंदबाजी की और उन्हें लगता है कि यह लाल एसजी गेंद की तुलना में अधिक स्विंग करती है। उन्होंने कहा, यह भारत में गुलाबी गेंद से दूसरा और फरवरी में पहला टेस्ट मैच होगा। इसलिए हम नहीं जानते कि यह कैसे व्यवहार करेगी। एंडरसन ने इसके साथ ही इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की रोटेशन (खिलाड़ियों को आराम देने की नीति) का समर्थन करते हुए आलोचकों से टीम के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए इसे विस्तृत तौर पर देखने को कहा है।

इंग्लैंड ने रोटेशन नीति के चलते जॉनी बेयरस्टॉ और मार्क वुड को भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों से बाहर रखा और अब आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए उनकी वापसी हुई है। विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर पहले टेस्ट मैच के बाद जबकि ऑलराउंडर मोईन अली दूसरे मैच के बाद स्वदेश लौट गये। एंडरसन ने कहा, आपको व्यापक तस्वीर पर गौर करना चाहिए। इसके पीछे विचार यह था कि अगर मैं उस टेस्ट (दूसरे मैच) में नहीं खेल पाया तो इससे मुझे गुलाबी गेंद से होने वाले टेस्ट के लिए अधिक फिट होकर मैदान पर उतरने का मौका मिलेगा।

वहीं इससे पहले केविन पीटरसन सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने ईसीबी की नीति की आलोचना की और कहा कि उसे भारत के खिलाफ इस बड़ी श्रृंखला में अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उतारने चाहिए।

धोनी के साथ एक और टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं उथप्पा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आईपीएल के 14 वें सत्र में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से खेलने जा रहे रॉबिन उथप्पा का सपना टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के संन्यास लेने से पहले उनके साथ एक और टूनार्मेंट जीतना है। उथप्पा ने पिछले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था। इस चेन्नई टीम के साथ जुड़ने के बाद उथप्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने चेन्नई टीम, उसके प्रशंसकों और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिल की बात कही है।

उन्होंने कहा कि वाणक्कम चेन्नई, कैसे हैं आप सबसे पहले, मुझे जो आप लोगों से प्यार मिला है। उसके लिए सीएसके के प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।

उथप्पा ने आगे कहा कि मेरे लिए यह किसी इच्छा के पूरे होने जैसी बात है। मैं एक बार फिर धोनी के साथ खेलना चाहता था और उनके रिटायर होने से पहले एक टूनार्मेंट जीतना चाहता हूं। उन्होंने इसके साथ ही सुरेश रैना और अंबाती रायडू के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने पर भी खुशी जताई है। उथप्पा 2007 में पहला टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया में शामिल थे। तब धोनी की कप्तानी में ही भारत ने यह खिताब जीता था। उथप्पा की यह छठी आईपीएल टीम है। इससे पहले वह राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पुणे वारियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं।

विश्व टेस्ट सीरीज जीतना है लक्ष्य : इशांत

नई दिल्ली। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने बुधवार से इंग्लैंड के साथ होने वाले दिन-रात्रि के मैच से पहले कहा है कि उनका लक्ष्य इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना है। इशांत बोले, मेरा ध्यान सिर्फ सीरीज जीतने और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने पर है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता हूं ऐसे में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप मेरे लिए विश्व कप के समान है। अगर हम इसे जीतेंगे तो ये विश्व कप या चैंपियंस ट्रॉफी जीतने जैसा ही होगा। महान ऑलराउंडर कपिल देव के बाद सौ टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बनने जा रहे इशांत ने कहा कि उनका टेस्ट करियर इतना लंबा इसलिये ही हो सका कि वह समझते थे कि कप्तान उनसे क्या चाहते हैं। इशांत ने बांग्लादेश के खिलाफ 18 वर्ष की उम्र में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। इसके बाद वह अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेले।

बिलिंग्स को गर्लफ्रैंड ने इसलिए गेंदबाज बनने कहा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए हुई नीलामी में इंग्लैंड के आक्रमक बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को अधिक कीमतें न मिलने पर उनकी गर्लफ्रैंड ने कहा है कि उसे अब गेंदबाज बन जाना चाहिये। बिलिंग्स ने सोशल मीडिया पर जो ट्वीट शेयर किया है। उस ट्वीट में बिलिंग्स अपनी गर्लफ्रैंड के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रैंड सारा ने मेरी और देखा और यह कहते हुए चली गई कि तुम एक गेंदबाज क्यों नहीं हो बिलिंग्स का यह ट्वीट फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह इसे खूब शेयर कर रहें हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मॉरिस को 16.25 करोड़ रूपए में खरीदा है। वहीं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काईल जैमीसन को 15 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया के झाय रिचर्डसन को 14 करोड़ रूपए मिले हैं। माना जा रहा है कि कि बिलिंग्स की गर्लफ्रैंड ने इसी कारण उन्हे तेज गेंदबाज बनने कहा हो। बिलिंग्स इंग्लैंड के अक्रामक बल्लेबाज हैं। वह चेन्नई की टीम की और से भी खेल चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के 17 मैचों में भाग लिया है। इन मैचों में सैम बिलिंग्स के बल्ले से उन्होंने 334 रन बनाए हैं। बिलिंग्स पारी की शुरूआत भी कर सकते हैं और मैच में फिनिशर भी बन सकते हैं। वह दिल्ली की टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते है अगर उन्हें अधिक मौके मिले। इस बार की आईपीएल नीलामी में फ्रैंचाईजियों ने गेंदबाजों पर अधिक पैसा खर्च किया है।

विजय हजारे ट्रॉफी : मध्यप्रदेश की लगातार दूसरी हार

इन्दौर, (एजेंसी)। मेजबान मध्य प्रदेश को विजय हजारे ट्रॉफी वन-डे क्रिकेट टूनार्मेंट में लगातार दूसरी शकिस्त खानी पड़ी। सोमवार को खेले गए मैच में विदर्भ ने मध्य प्रदेश को 4 विकेट से शकिस्त दी। इन्दौर में खेले गए दो अन्य लीग मुकाबलों में झारखंड व आंध्र प्रदेश ने अपने-अपने मैच जीते, दोनों टीमों की स्पर्धा में यह लगातार दूसरी जीत है।

एमरल्ड हाईट्स स्कूल के आम्रकूट मैदान पर खेले गए एलिट ग्रु-बी के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए म.प्र. ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में विदर्भ ने 48.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 246 रनों के साथ विजयी लक्ष्य पार कर लिया। लक्ष्य भेदने उतरे विदर्भ के बल्लेबाजों ने अपने संयुक्त प्रयासों से टीम की जीत आसान कर दी। कप्तान व सलामी बल्लेबाज फैज फजल (43) ने संजय रघुनाथ रामास्वामी (32) के साथ पहले विकेट के लिए 63 रन और गणेश सतीश (47) के साथ दूसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। धीमी रनगति से विदर्भ 28.2 ओवर में अपने 100 रन पूरे कर सका। कुमार कार्तिकेय सिंह ने कप्तान फजल को भंडारी के हाथों पहला झटका दिया, इसके बाद संजय रघुनाथ को रन-आउट कर चलता किया, इसके बाद शुभम शर्मा ने गणेश सतीश को पार्थ के हाथों झलिवाया। अक्षय वाडेकर (11) के पार्थ के हाथों रन-आउट होने के बाद यश राठौड़ ने आदित्य सरवटे साथ विदर्भ की रन गति को बढ़ाया और टीम को 200 के पार पहुंचाया। यश राठौड़ (39) के रन-आउट होने के बाद आदित्य सरवटे (39*) व दर्शन नलकंडे (19*) ने नाबाद रहते हुए टीम को 48.5 ओवर में 246 रनों के साथ जीत दिला दी। इससे पहले मेजबान म.प्र. की ओर से श्रीवास्तव (52 रन) व कप्तान पार्थ सहानी (68 रन नाबाद) ने अर्द्धशतकीय पारी खेली, जबकि अभषिक भंडारी (31), शुभम शर्मा (36), रजत पाटीदार (38) सस्ते में समिट गए, जबकि निचले क्रम के शेष बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी छू न सके। विदर्भ के लिए सरवटे ने 3 विकेट लिए, जबकि ठाकरे, नलकंडे व दुबे को 1-1 विकेट मिला। अंक तालिका की बात करें तो मध्य प्रदेश की टीम ग्रुप-बी में अपने दोनों मैच हारकर अंतिम छठे स्थान पर है। वहीं विदर्भ की टीम 2 मुकाबलों में पहली जीत के साथ 4 अंकों के साथ तीसरे क्रम पर है। जबकि झारखंड और आंध्रप्रदेश की टीम अपने दोनों मैच जीतकर क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर हैं।

होलकर स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने सितारा खलिाड़ियों से भरी तमिलनाडु को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले खेलते हुए तमिलनाडु ने 41.3 ओवर में मात्र 176 रन ही बना सकी। तमिलनाडु के लिए बाबा अपराजित ने सर्वाधकि 40 रन बनाए, सांई किशोर ने 29 व सोनू यादव ने 37 रनों का योगदान दिया, जबकि कप्तान दिनेश कार्तिक 7 रन ही बना सके। जवाब में अश्विन हेब्बर (101 रन) की नाबाद शतकीय पारी बदौलत आंध्रप्रदेश ने मात्र 29.1 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल की। रिकी भुई 52 रन बनाकर नाबाद रहे।

इन्दौर में खेले गए एक अन्य मुकाबले में पंजाब को 2 रनों से हराकर झारखंड ने लगातार दूसरी जीत अपने नाम की। झारखंड की टीम ने 9 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 45.5 ओवर में 215 रनों पर सिमट गई। शुरूआती मुकाबले में विस्फोटक पारी खेलने वाले झारखंड के कप्तान इशान किशन का इस मैच में नहीं चला और वो मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। उत्कर्ष सिंह (51 रन) और शाहबाज नदीम (45 रन नाबाद) ने उम्दा पारी। जवाब में पंजाब अभषिक शर्मा (56 रन) और कप्तान मनदीप सिंह (68 रन) की उम्दा अर्द्धशतकीय पारी के बावजूद यह मुकाबला मात्र 2 रनों गवां बैठी।

इटालियन फुटबॉल लीग में रोनाल्डो के दो गोल से जीता युवेंट्स

तूरिन, (एजेंसी)। इटली के फुटबॉल क्लब युवेंटस ने इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में क्रोटोन को 3-0 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो शानदार गोलों की सहायता से युवेंटस को यह जीत मिली। रोनाल्डो ने पहले हाफ के 38वें मिनट में पहला गोल किया और फिर इंजुरी टाइम में दूसरा गोल करके युवेंटस को मध्यांतर तक 2-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद वेस्टन मैकेनी ने 66वें मिनट में एक गोल कर युवेंटस की बढ़त को और पक्का कर दिया। इस जीत से युवेंटस की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गयी है। इसके बाद भी वह शीर्ष पर चल रहे इंटर मिलान से आठ अंक पीछे है। इंटर मिलान के 23 मैचों में 53 और युवेंटस के 22 मैचों में 45 अंक हैं। क्रोटोन की यह लगातार पांचवीं हार है और उस पर दूसरे डिवीजन में खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। युवेंटस का मनोबल इस जीत से अगले मुकाबले के लिए बढ़ा है।

इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलते हुए डेनी वेलबेक व टायरिक मिटसेल।

सहायक कोच थोर्प ने स्टोक्स का हौंसला बढ़ाया

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारतीय टीम के साथ बुधवार को शुरू हो रहे दिन-रात्रि के तीसरे टेस्ट में पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही मेहमान टीम इंग्लैंड की चिन्ता अपने स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को लेकर है। स्टोक्स अब तक भारतीय टभ्म के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को खेलने में विफल रहे हैं। वहीं टीम के सहायक कोच सहायक ग्राहम थोर्प ने स्टोक्स का हौंसला बढ़ाते हुए कहा है कि उसमें गेंदबाजों को बैकफुट पर लाने की पूरी क्षमता है जो उसे भूलनी नहीं चाहिये। पहले दो टेस्ट में अश्विन ने तीन बार स्टोक्स को आउट किया। इस बारे में थोर्प ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है। स्टोक्स की खेलने की शैली कई बार अलग-अलग होती है। वह पारी का सूत्रधार भी बन सकता है। उसमें गेंदबाजों को बैकफुट पर लाने की क्षमता है और उसे यह भूलना नहीं चाहिए। दोनो ही टीमों के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज इस समय 1-1 से बराबरी पर है। अश्विन की सराहना करते हुए थोर्प ने कहा कि वह काफी खतरनाक गेंदबाज है और स्पिनरों की सहायक पिच पर तो उसे खेलना और भी अधिक कठिन हो जाता है। सहायक कोच ने माना कि आने वाले मुकाबले काफी कठिन होंगे जिसके लिए टीम को तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को साफ तौर पर पता होना चाहिए कि वह अपने प्रदर्शन में सुधार कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ीयों को अपने बेसिक्स पर ध्यान देकर संयम से खेलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चोट के कारण पहले दो टेस्ट से बाहर रहे जैक क्राउली समेत सभी खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध हैं।

इशांत ने टेस्ट करियर लंबा होने का कारण बताया

अहमदाबाद, (एजेंसी)। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर के लंबे होने का कारण बताते हुए कहा है कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि वह समझते थे कि कप्तान उनसे क्या चाहते हैं। इसके साथ ही कहा कि उन्हें पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान से भी काफी कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा मैंने अपनी फिटनेस पर भी काम किया जिसका भी मुझे फायदा मिला है। इशांत ने बांग्लादेश के खिलाफ 18 वर्ष की उम्र में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था।

इसके बाद वह अनिल कुंबले, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेले। इशांत इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में बुधवार से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में उतरने के साथ ही अपाना 100वां टेस्ट खेलेंगे। यह भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट है.

वहीं कौना सा कप्तान उन्हें अच्छी तरह समझ सका। इस सवाल पर इशांत ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले यह कहना मुश्किल है कि कौन मुझे सबसे अच्छा समझ सका, लेकिन सभी मुझे अच्छे से समझते थे। कप्तान मुझे कितना समझते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं कप्तान को कितना समझता हूं। यह भी काफी अहम है कि कप्तान मुझसे क्या चाहते हैं। अब तक 99 टेस्ट में 302 विकेट ले चुके इशांत सीमित ओवरों की टीम की हिस्सा नहीं है और आईपीएल में भी कुछ सत्र बाहर रहे। इस कारण भी उनका टेस्ट करियर लंबा हुआ है।

इशांत ने कहा, मैं इसे वरदान की तरह लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलना नहीं चाहता, लेकिन जब खेलने का मौका नहीं हो तो सबसे अच्छा है कि अभ्यास जारी रखे। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि वनडे में चयन नहीं होने से टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन पर असर पड़े। कम से कम मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं एक प्रारूप तो खेल रहा हूं। इशांत ने यह भी कहा, इसके यह मायने नहीं है कि अगर तीनों प्रारूप खेलता तो मैं सौ टेस्ट नहीं खेल पाता। शायद थोड़ा समय ज्यादा लगता। मैं 32 साल का हूं, 42 का नहीं।